वर्ष-11, अंक-7, मई-2026

मूल्य: ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

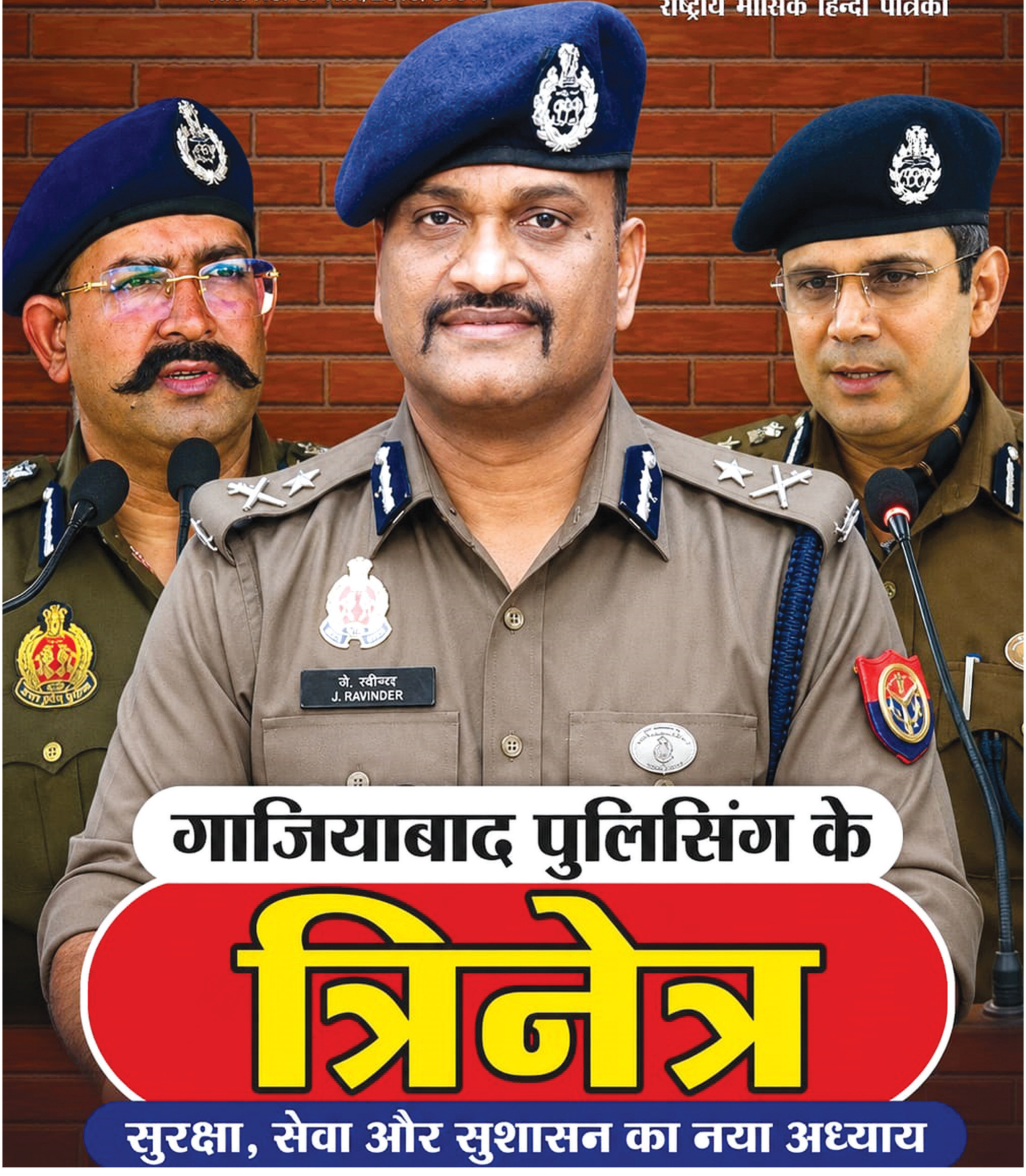

गाजियाबाद पुलिसिंग के

त्रिनेत्र

सुरक्षा, सेवा और सुशासन का नया अध्याय

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शक्ति से समृद्धि

नारी
उत्तर प्रदेश
के विकास
की धुरी

नवनिर्माण के 9 वर्ष

सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त

निराश्रित महिलाओं को पेंशन

लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति

महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%

1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार

कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण

10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

अन्दर के पेजों में...

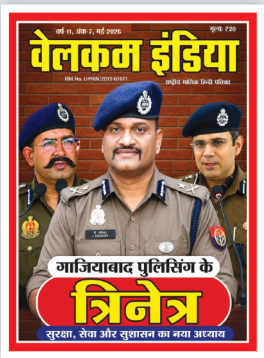

वर्ष- 11 अंक- 8

मई-2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

प्रेरणा स्रोत
स्व. वेद प्रकाश शर्मा

संरक्षक
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोड़ा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

कवर स्टोरी पेज-28

गाजियाबाद के कायाकल्प के 'शिल्पी' विक्रमादित्य सिंह मलिक पेज 03

विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा पेज 05

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के विजनरी नेतृत्व में विकास और संरक्षण का अद्भुत संगम पेज 12

महिला कोटे से जुड़े संविधान बिल के लुढ़कने के सियासी निहितार्थ पेज 26

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कब्जा! पेज 53

ऋषि सुनक भी हुए फैन: 11 साल की बोधाना ने रचा इतिहास पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

दो-तिहाई का खेल और दलबदल कानून की घटती प्रासंगिकता

देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक दल को छोड़ कर दूसरे में शामिल होने को लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखा जाता है। मगर सच यह भी है कि जब जनप्रतिनिधियों ने सिद्धांतों के बजाय सुविधा के मुताबिक पार्टी बदलने को एक आम चलन बनाना शुरू कर दिया, तब इस पर लगाम लगाने की जरूरत पड़ी और इसी क्रम में दल-बदल विरोधी कानून अस्तित्व में आया। विडंबना यह है कि इस कानून के लागू होने के बावजूद अलग-अलग कारणों का हवाला देकर विधायकों या सांसदों के पाला बदलने या दूसरी पार्टियों में शामिल होने के मामले आए दिन सामने आते रहे हैं।

मगर इस बार आम आदमी पार्टी से जुड़े राज्यसभा के सात सांसदों ने जिस तरह अपने दल को छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की घोषणा की है, उसने एक बार फिर राजनीति में नैतिकता और दल-बदल कानून की प्रासंगिकता पर बहस छेड़ दी है। गौरतलब है कि राज्यसभा में आप के दस सांसद थे। उनमें से राघव चड्ढा सहित सात सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। उनका मानना है कि चूंकि अलग होने वाले सांसदों की संख्या दो-तिहाई की कसौटी पर पूरी है, इसलिए दल-बदल विरोधी कानून के तहत यह गलत नहीं है। संभव है कि आप छोड़ कर भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं के लिए सिर्फ कानून के प्रावधानों पर खरा उतरना ही किसी कार्रवाई से बचने के लिए काफी है, लेकिन सवाल है कि क्या केवल तकनीकी तौर पर सही होकर ही खुद को नैतिकता की कसौटी पर भी उचित मान लिया जा सकता है! खैर, आम आदमी पार्टी की ओर से संबंधित सातों सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करने की बात कही गई है। हवाला यह दिया गया है कि दल-बदल कानून में राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार का विभाजन या गुटबंदी करने पर स्पष्ट तौर पर मनाही की गई है, भले ही वहां दो-तिहाई बहुमत हो।

जाहिर है, आप के नेता अब दल-बदल से संबंधित कानूनी बारीकियों के मुताबिक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। मगर यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर मान्यता का मुद्दा उठने पर अंतिम फैसला क्या आता है। एक सवाल अपना दल छोड़ कर सांसदों के भाजपा में शामिल होने और पार्टी के रूप में विलय से जुड़े संदर्भ का भी उठेगा।

हालांकि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा की राजनीतिक सक्रियता जिस तरह उलझी हुई दिख रही थी, उसके मद्देनजर पहले से ही उनके पार्टी से बाहर होने की संभावना जताई जा रही थी। मगर उनके साथ जिस तरह छह अन्य नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उसे लेकर राजनीतिक हलके में थोड़ी हैरानी जताई जा रही है। देश की राजनीति में बिना किसी सैद्धांतिक आधार के सुविधा के मुताबिक पार्टी बदलने की प्रवृत्ति और इसके सहारे सरकारों की स्थिरता के प्रभावित होने के हालात को रोकने के लिए दल-बदल कानून बनाया गया था। मगर पिछले कुछ वर्षों से इस कानून के तहत मिली छूट का लाभ उठा कर कई राज्यों में जिस तरह सरकारें बदली गईं, उसमें कहीं भी सैद्धांतिक कसौटी का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे अनेक मामले सामने आए, जिसमें सिर्फ परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए विचारधारात्मक प्रतिबद्धता के सवाल को दरकिनार कर दिया गया और ऐसे नेताओं के लिए दल-बदल कानून कोई बाधा नहीं बना। इसी क्रम में आप के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर फिर यह सवाल उठा है कि आखिर दल-बदल कानून की प्रासंगिकता क्या रह गई है।

ललित कुमार
सम्पादक

खैर, आम आदमी पार्टी की ओर से संबंधित सातों सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करने की बात कही गई है। हवाला यह दिया गया है कि दल-बदल कानून में राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार का विभाजन या गुटबंदी करने पर स्पष्ट तौर पर मनाही की गई है, भले ही वहां दो-तिहाई बहुमत हो।

प्रशासक, खिलाड़ी और विजनरी...

गाजियाबाद के कायाकल्प के 'शिल्पी'

विक्रमादित्य सिंह मलिक

ललित कुमार

उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त और औद्योगिक शहरों में शुमार 'गाजियाबाद' आज एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। धूल, धुएं और भीड़भाड़ वाले शहर की पहचान अब 'स्मार्ट और सस्टेनेबल' सिटी के रूप में हो रही है। इस बदलाव के केंद्र में है एक युवा, ऊर्जावान और खेल भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व विक्रमादित्य सिंह मलिक (IAS)। वर्तमान में गाजियाबाद के नगर आयुक्त के रूप में कार्यरत विक्रमादित्य ने न केवल फाइलों के बोझ को कम किया है, बल्कि शहर की नसों में विकास का नया रक्त संचारित किया है।

पारिवारिक विरासत और प्रारंभिक संघर्ष, सादगी से सफलता का सफर

विक्रमादित्य सिंह मलिक का व्यक्तित्व उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिंब है। चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक परिवार में जन्मे विक्रमादित्य के रगों में जनसेवा की भावना विरासत में मिली है। उनके पिता, युद्धवीर सिंह मलिक

शिक्षा और लॉ से आईएएस तक का सफर

विक्रमादित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही यह साबित कर दिया था कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ-साथ वे खेलों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित नालसार यूनिवर्सिटी, हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की। वकालत के पेशे में कदम रखा और एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में अनुभव भी लिया। लेकिन साल 2012 में उनकी बहन के आईएएस बनने के बाद, उनके भीतर की जनसेवा की लौ और तेज हो गई। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था। दो बार की असफलता ने उन्हें निराश जरूर किया, लेकिन उनकी 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' ने उन्हें हार नहीं मानने दी। साल 2017 में उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 48वीं रैंक हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया।

(IAS), हरियाणा कैडर के एक दिग्गज अधिकारी रहे हैं, जिनकी कार्यशैली की छाप विक्रमादित्य पर स्पष्ट दिखती है। उनकी माता एक प्रख्यात लेखिका हैं, जिनसे उन्हें रचनात्मक सोच और संवेदनशीलता मिली।

'ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025' और ग्लोबल पहचान

विक्रमादित्य सिंह मलिक की सबसे बड़ी वैश्विक उपलब्धि तब आई जब गाजियाबाद का चयन प्रतिष्ठित 'ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025' के लिए हुआ। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। उनका विजन था 'ऑर्गेनिक वेस्ट' यानी गीले कचरे को 'व्हाइट रूफटॉप पेंट' में बदलना। यह इनोवेशन न केवल कचरा प्रबंधन का समाधान देता है, बल्कि शहरों के तापमान को कम करने में भी क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट ने गाजियाबाद को दुनिया के नक्शे पर एक 'इनोवेटिव सिटी' के रूप में स्थापित कर दिया है।

गाजियाबाद की वायु पर 'विजय' प्रदूषण के विरुद्ध जंग

जब विक्रमादित्य सिंह मलिक ने गाजियाबाद नगर निगम की कमान संभाली, तो सबसे बड़ी चुनौती थी शहर की हवा। गाजियाबाद अक्सर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहता था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत मिशन के तौर पर लिया।

मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग: उन्होंने धूल से निपटने के लिए आधुनिक सड़कों की सफाई और पेड़ों पर पानी के छिड़काव को एक नियमित प्रक्रिया बनाया।

ग्रीन कवर का विस्तार: शहर के डिवाइडरों, पार्कों और खाली पड़ी जमीनों पर सघन पौधारोपण अभियान चलाकर उन्होंने 'ग्रीन गाजियाबाद' की नींव रखी।

GRAP का कड़ाई से पालन: निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपायों और कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाइयों ने गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार दिखाया।

अतिक्रमण मुक्त गाजियाबादः 'अवैध' पर प्रहार, 'विकास' को विस्तार

शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना किसी चुनौती से कम नहीं था। विक्रमादित्य ने 'अपील और एक्शन' का रास्ता चुना।

अवैध रैंप और अतिक्रमणः उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, उन्हें शहर के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाई और फिर जहां जरूरत पड़ी, वहां निगम का बुलडोजर चलाकर सड़कों को चौड़ा और सुगम बनाया।

सिस्टम में पारदर्शिताः हाउस टैक्स और व्यावसायिक कर की प्रणालियों को सरल और डिजिटल बनाकर उन्होंने भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म किया। 15 मार्च तक कर छूट की नीतियों को स्पष्ट कर उन्होंने आम जनता को बड़ी राहत दी।

नाम : विक्रमादित्य सिंह मलिक (IAS 2017)
रैंक : 48वीं (ऑल इंडिया)
शिक्षा : कानून में स्नातक (NALSAR, हैदराबाद)
प्रमुख पद : मुख्य विकास अधिकारी (CDO), नगर आयुक्त (गाजियाबाद)
विशेष उपलब्धि : ब्लूमबर्ग मेयर चैलेंज 2025 में चयन।
हॉबी : लॉन टेनिस (नेशनल सिविल सर्विसेज प्लेयर)
मूल मंत्र : 'समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनिए।'

खेलों के प्रति अटूट प्रेम, फाइलों के बीच 'लॉन टेनिस' की चमक

काम के भारी दबाव और घंटों की बैठकों के बावजूद, विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अपने भीतर के खिलाड़ी को कभी मरने नहीं दिया। वे मानते हैं कि खेल हमें अनुशासन और टीम वर्क सिखाते हैं, जो प्रशासन के लिए अनिवार्य है। हाल ही में उनका चयन नेशनल सिविल सर्विसेज की यूपी टीम के लिए हुआ है। वे लॉन टेनिस में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बचपन का पसंदीदा खेल 'लॉन टेनिस' अब उनके तनाव को कम करने का जरिया और फिटनेस का आधार है। एक आईएएस अधिकारी का खेल के प्रति यह समर्पण शहर के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

जन-सुनवाई और संवेदनशीलता, जनता का 'अपना' अधिकारी

नगर आयुक्त के रूप में विक्रमादित्य केवल ऑफिस तक सीमित नहीं रहते। वे सुबह-सुबह सड़कों पर उतरकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हैं और 'जनता दर्शन' के माध्यम से सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं। चाहे वह कूड़ा निस्तारण की समस्या हो या स्ट्रीट लाइट की, उनके पास हर समस्या का एक 'टाइम-बाउंड' समाधान होता है। विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में गाजियाबाद नगर निगम आज एक 'सर्विस प्रोवाइडर' की तरह काम कर रहा है। उनकी कार्यशैली में कानून की बारीकी, प्रशासन की दृढ़ता और एक खिलाड़ी का धैर्य नजर आता है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि नीयत साफ हो और विजन वैश्विक, तो किसी भी शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। गाजियाबाद के लिए विक्रमादित्य का कालखंड 'स्वर्ण अक्षरों' में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने शहर को केवल सुविधाएं नहीं दीं, बल्कि उसे एक 'आत्मसम्मान' और 'वैश्विक पहचान' भी दी है।

विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा और सत्ता के नए समीकरण

उज्जवल रस्तौगी

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। केरल से लेकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। रैलियों की गूंज, वादों की बरसात और आरोप-प्रत्यारोप के तीखे तीरों के बीच लोकतंत्र का यह उत्सव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे, घोषणापत्र और रणनीति के साथ मैदान में है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने का साधन नहीं बल्कि बीते पांच वर्षों के कामकाज का जनमत संग्रह और आने वाले राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण है।

इन पांच राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 116 लोकसभा सीटों के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह राजनीतिक रणक्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है, असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बार का चुनावी परिदृश्य कई स्तरों पर जटिल और बहुआयामी है। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास

कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और 'डबल इंजन' जैसे नारों के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक खामियों को मुद्दा बनाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यह संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा बल्कि विचारधारा, नीतियों और विकास के मॉडलों की प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 6.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था जबकि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा 'डबल इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यहां मुकाबला बेहद कांटे का होगा, एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत दांव पर है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का सुनहरा अवसर है।

> **इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा 'डबल इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है।**

असम का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में 2.25 करोड़ मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यहां मुख्य सवाल यही है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। वहीं विपक्ष सीएए-एनआरसी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता ने इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। असम में परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूर्वोत्तर भारत में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेंगे।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन महंगाई, बिजली संकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना एक नया समीकरण बना सकता है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच।

केरल में 140 सीटों के लिए 2.7 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। यहां का चुनाव पारंपरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। इस बार यदि वह तीसरी बार सत्ता में आता है तो यह एक नया राजनीतिक अध्याय होगा। वाम मोर्चा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मॉडल को प्रमुखता दे रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला

यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है।

पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहां की राजनीति बेहद संवेदनशील और निर्णायक है।30 सीटों वाली विधानसभा में 9.44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहां गठबंधन राजनीति का महत्व सबसे अधिक है, जहां छोटे-छोटे वोट अंतर भी सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी राज्यों में एक समान बात यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों का समीकरण हमेशा सीधा नहीं होता।

कई बार मामूली वोट अंतर भी भारी सीट अंतर में बदल जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने चुनावी अभियान को एक नई दिशा दी है, जहां नैरेटिव की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है।

चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार कोई एक मुद्दा हावी नहीं है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप में सामने आ रहे हैं।यही विविधता इन चुनावों को और अधिक जटिल और रोचक बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाली 116 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि भाजपा असम में अपनी पकड़ बनाए रखती है, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है और दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करती है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। वहीं, यदि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखती है तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की प्रमुख धुरी बनी रह सकती हैं। केरल में वाम मोर्चे की जीत वामपंथी राजनीति के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी जबकि तमिलनाडु में डीएमके की निरंतरता द्रविड़ राजनीति की दिशा तय करेगी।

कुल मिलाकर, यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। मतदाता इस बार खामोश जरूर हैं लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर गहराई से सोच-विचार और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि किसने जनता की अपेक्षाओं को समझा और किसे आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र का यह महापर्व एक बार फिर यह सिद्ध करने जा रहा है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और वही निर्णय देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है।

मुश्किल के समय भारत बना पड़ोसियों के लिए संकटमोचक

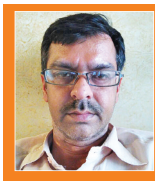
संजीव कुमार

दक्षिण एशिया की राजनीति में अचानक आया यह मोड़ किसी भूचाल से कम नहीं है। कुछ महीने पहले तक भारत को घेरने की साजिश रचने वाले पड़ोसी देश आज उसी भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने पूरे क्षेत्र की असलियत उजागर कर दी है। जो देश कभी 'इंडिया आउट' का नारा लगा रहे थे, आज वही भारत से तेल और गैस की मदद मांग रहे हैं। यह सिर्फ कूटनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का निर्णायक पल है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा एशिया के देशों के लिए होता है। ईरान युद्ध ने इस जीवनरेखा को झकझोर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश ऊर्जा निर्भरता के दलदल में फंस गए हैं। भारत भी आयात पर निर्भर है, लेकिन उसकी रणनीतिक तैयारी और संतुलित कूटनीति ने उसे संकट में भी मजबूत बनाए रखा है। ईरान ने भारत को मित्र मानते हुए तेल और रसोई गैस के जहाजों को रास्ता दिया, जो भारत के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने पड़ोसियों को संकट से निकालने का बीड़ा उठाया। यही है भारत की 'पड़ोस पहले' नीति का असली चेहरा, जो केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। हम आपको बता दें कि युद्ध से उपजे संकट का बांग्लादेश सबसे बड़ा शिकार बना है। अपनी जरूरत का 95 प्रतिशत तेल और तीस प्रतिशत गैस आयात करने वाला यह देश अब अंधेरे में डूब रहा है। बिजली कटौती, उद्योगों का ठप होना और विश्वविद्यालयों का बंद होना इस बात का सबूत है कि ऊर्जा संकट किसी देश की रीढ़ कैसे तोड़ सकता है। कपड़ा उद्योग, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जान है, इस समय डीजल की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने भारत की ओर रुख किया और भारत ने बिना देरी किए

इसके अलावा, भारत ने मानवीय सहायता को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। रणनीतिक रूप से देखें तो यह भारत के लिए सुनहरा मौका है। ऊर्जा आपूर्ति के जरिए भारत न केवल अपने पड़ोसियों को स्थिर कर रहा है, बल्कि उनके भीतर अपनी विश्वसनीयता भी मजबूत कर रहा है।

मदद का हाथ बढ़ाया। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति तेज कर दी गई। हजारों टन ईंधन भेजा गया और आगे भी आपूर्ति जारी है। हम आपको याद दिला दें कि यह वही बांग्लादेश है जहां हाल ही में भारत विरोधी माहौल चरम पर था और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। लेकिन संकट ने उसे सच्चाई दिखा दी कि असली सहारा कौन है। मालदीव का मामला और भी दिलचस्प है। एक साल पहले तक भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहरीली भाषा बोलने वाले इस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु आज भारत को 'विश्वसनीय साथी' बता रहे हैं।

हम आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति मुइज्जु ने सत्ता में आते ही भारतीय सैनिकों को देश से बाहर कर दिया था और चीन की तरफ झुकाव दिखाया था। लेकिन जैसे ही ऊर्जा संकट और पर्यटन पर असर पड़ा, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के लिए मालदीव को वही भारत याद आ रहा है। श्रीलंका की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। 2022 के आर्थिक पतन की यादें अभी ताजा हैं। उस समय चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत उसे भारी पड़ी थी। अब फिर वही स्थिति बन रही है। ऊर्जा जरूरत का साठ प्रतिशत आयात करने वाला श्रीलंका एक महीने से ज्यादा का भंडारण भी नहीं रख पाता। उसे ईंधन के दाम तैंतीस प्रतिशत तक बढ़ाने पड़े हैं। ऐसे समय में भारत ने एक बार फिर 'पहला सहायक' बनकर दिखाया। हजारों टन पेट्रोल और डीजल तुरंत भेजा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से भारत का आभार जताया। यह केवल सहायता नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत है कि संकट के समय कौन साथ खड़ा होता है। दक्षिण एशिया के इस बदलते परिदृश्य में नेपाल का जिक्र भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह वह पड़ोसी है जहां भारत की मदद लगातार और बिना किसी शोर के पहुंच रही है। ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत ने नेपाल को ईंधन और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। दरअसल, हिमालयी भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण नेपाल पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है और ऐसे समय में भारत की स्थिर सप्लाई लाइन उसके लिए जीवनरेखा बनी हुई है। यह संबंध केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भरोसे और पारस्परिक सहयोग का प्रतीक है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व बेहद गहरा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा की धुरी वही है। साथ ही यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती है। जिन देशों ने चीन के भरोसे अपनी नीतियां बनाई थीं, वह अब भारत की ओर लौट रहे हैं। इसके अलावा, भारत ने मानवीय सहायता को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। रणनीतिक रूप से देखें तो यह भारत के लिए सुनहरा मौका है। ऊर्जा आपूर्ति के जरिए भारत न केवल अपने पड़ोसियों को स्थिर कर रहा है, बल्कि उनके भीतर अपनी विश्वसनीयता भी मजबूत कर रहा है। यह भविष्य में सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। बहरहाल, यह साफ है कि भाषण और नारे अपनी जगह हैं, लेकिन भूगोल और जरूरतें अपनी जगह। संकट के समय वही देश मायने रखता है जो मदद कर सके। और इस परीक्षा में भारत न केवल पास हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र का केंद्र बनकर उभरा है। यही नया दक्षिण एशिया है, जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुका है। खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अगर किसी एक नेतृत्व की छाप सबसे स्पष्ट दिखती है, तो वह है प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर रणनीति और दूरदर्शिता के साथ फैसले लिए हैं।

जहां एक तरफ पड़ोसी देश कभी भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे, वहीं आज वही देश भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, बल्कि लगातार संवाद, सहायता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। मोदी की नीति ने यह साबित कर दिया है कि सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन ही असली कूटनीति है। आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि संकट में भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है और यह उपलब्धि सीधे तौर पर मोदी की रणनीतिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा है।

पीलीभीतः प्रकृति का गौरव और प्रगति का नया अध्याय

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के विजनरी नेतृत्व में विकास और संरक्षण का अद्भुत संगम

लुकमान

उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर अंकित जनपद पीलीभीत, अपनी मिट्टी की सोंधी खुशबू और बांसुरी की सुरीली धुन के लिए तो विख्यात रहा ही है, लेकिन आज इसकी पहचान का फलक कहीं अधिक विस्तृत हो चुका है। हिमालय की तलहटी में बसा यह जनपद आज एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जहां एक ओर 730 वर्ग किलोमीटर में फैला पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) अपनी प्राकृतिक जैव-विविधता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर

जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में यह जिला आधुनिक विकास की नई गाथा लिख रहा है।

हरियाली की गोद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व

साल 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद, पीलीभीत ने वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर अपनी जगह बनाई। यहां के घने 'साल' के वन और तराई के घास के मैदान न केवल बाघों के लिए एक आदर्श आवास हैं, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए भी फेफड़ों का काम करते हैं, यहां केवल बाघ ही नहीं, बल्कि दुर्लभ बारहसिंगा, तेंदुआ, पाढ़ा, और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। शारदा और खन्नौत जैसी नदियों का सानिध्य इसे एक जलीय स्वर्ग भी बनाता है। रोजगार और संरक्षण का सेतु पीलीभीत का चूका बीच (Chuka Beach) आज पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका

है। जंगल की शांति और वन्यजीवों की झलक पाने के लिए आने वाले पर्यटकों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा दी है। होमस्टे से लेकर स्थानीय गाइडों तक, यहां का पर्यटन अब जन-जन की आय का स्रोत बन रहा है।

नेतृत्व की कमान, जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का दूरदर्शी दृष्टिकोण

प्रशासनिक दक्षता और जन-संवाद का नया मॉडल

किसी भी जनपद की प्रगति का पहिया उसके प्रशासनिक मुखिया की सोच पर निर्भर करता है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पीलीभीत की कमान संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया कि विकास केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर उतरेगा।

कानून व्यवस्था और पारदर्शिता

एक सुरक्षित समाज ही विकास की नींव रख सकता है। जिलाधिकारी ने जिले में कानून

व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक और मानवीय संवाद का अनूठा मेल स्थापित किया है। थानों की कार्यप्रणाली से लेकर राजस्व मामलों के निपटारे तक, उनके कड़े रुख ने अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास पैदा किया है।

जनसुनवाई, समस्या का त्वरित समाधान

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सुलभता है। नियमित जनसुनवाई के माध्यम से वे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा सुनते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षणों ने विभागों में कार्य-संस्कृति को बदला है। अब कर्मचारी कार्यालयों में समय पर मिलते हैं और फाइलों की पेंडेंसी कम हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की नींव

जिलाधिकारी का विशेष ध्यान सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतरी पर रहा है। 'मिशन कायाकल्प' के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है।

संपादक की राय

प्रशासनिक इच्छाशक्ति और प्राकृतिक संपदा का यदि सही मेल हो जाए, तो कोई भी जनपद आदर्श बन सकता है। पीलीभीत इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की सराहना केवल उनके पद के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए जमीनी बदलावों के कारण होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में पीलीभीत न केवल सुरक्षित है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है।

विकास और पर्यावरण, एक अनूठा संतुलन

अक्सर विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। प्रशासन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आधारभूत ढांचे (सड़क, बिजली, पानी) का विकास करते समय पीलीभीत की प्राकृतिक संपदा को कोई नुकसान न पहुंचे। सड़कों के जाल से लेकर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन तक, हर योजना में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीलीभीत को ओडीएफ प्लस श्रेणी में बनाए रखने और कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को अपनाने में प्रशासन की सक्रियता सराहनीय है।

योजनाओं का धरातल पर उतरना

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा का ध्यान रखते हुए ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष बल दिया गया है, वहीं पीलीभीत एक कृषि प्रधान जिला है। किसानों को समय पर खाद, बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।

पीलीभीत आज एक ऐसे दौर में है जहां वह अपनी प्राचीन पहचान (बांसुरी और तराई) को संजोते हुए आधुनिक भारत की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है। एक तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार है, तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह जैसा सक्षम नेतृत्व है, जो जिले को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।

नोएडा मजदूर आंदोलनः आखिर कौन जिम्मेदार ?

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है।

हमारे देश के राजनेता भले ही चुनावों के दौरान दलित-महादलित-आदिवासी, ओबीसी-ईबीसी, अल्पसंख्यक-पसमांदा और गरीब सवर्ण आदि से जुड़े सामाजिक न्याय सम्बन्धी तरह-तरह की बातें करते हैं, ममनगढ़ंत आंकड़े गिनाते/बताते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे श्रमजीवियों का अंतहीन शोषण होता रहता है, जिससे उनका मुंह फेरे रहना या फिर किसी बड़े आंदोलन के बाद सक्रिय होना उनके नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाता है।

हरेन्द्र शर्मा

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है।

यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निमार्ता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं। विपक्ष का काम संसद में, विधान मंडल में इन्हीं पहलुओं पर तर्कसंगत बहस करना है, लेकिन वह भी नीतिगत नकारापन का शानदार नमूना बन चुका है।

दिलचस्प तो यह कि पहले सत्ताधारी यूपीए के वक्त एनडीए विपक्ष में था और अब सत्ताधारी एनडीए के वक्त यूपीए/इंडिया गठबंधन विपक्ष में है।

चूंकि दोनों पूंजीवादी गठबंधन हैं और अपने आर्थिक मोहपाश में जनोन्मुखी समाजवादी व वामपंथी सियासत को बांध चुके हैं, जिससे सबकुछ गड्डमड्ड हो चुका है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद और कहीं सम्प्रदायवाद के नाम पर परस्पर बंटी हुई जनता को अपनी मौलिक जरूरतों का एहसास ही नहीं है।

काबिलेगौर है कि शहरों/महानगरों या गांवों में जो आमतौर पर वेतन स्ट्रक्चर होता है, उससे कोई युवा या वयस्क अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सकता है क्या? जवाब होगा- संभव नहीं! कोढ़ में खाज यह कि तरह तरह के मित्रों- शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र आदि के मार्फत सरकारी क्षेत्र भी इन्हीं पूंजीवादी मानसिकता को तरजीह देता आया है, जिस पर उदार हृदय से बहस करने और भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है।

सवाल है कि जिन शहरों में फ्लैट्स या जमीन की कृत्रिम कीमतें आसमान छूती हों, वहां के दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी, अंशकालिक/पूर्णकालिक श्रमिकों के वेतनमान, और भारतीय कानूनों से अधिकारियों/उद्योगपतियों के खिलवाड़ से पूरी श्रम व्यवस्था विस्फोटक कगार पर खड़ी है। शहरों में बढ़ता झुग्गी-झोपड़ी कल्चर किसी नैतिक महामारी जैसा प्रतीत होता है।

सुलगता सवाल है कि निजी क्षेत्र में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं निजी कम्पनियों में मिलती है। प्रोपर्टी इंडस्ट्री की तरह आधा ब्लैक सैलरी और आधा व्हाइट सैलरी वाली आंखों में धूल झोंकने वाली व्यवस्था से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सरकारी क्षेत्रों की तरह आवासीय सुविधाओं से निजी क्षेत्र के श्रमिकों को वंचित क्यों रखा जाता है? नौकरी बाजार में श्रम ठेकेदार पैदा करने से किसके हित सधते हैं? सवाल अनेक हैं, लेकिन उत्तर एक- राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक सांठगांठ से जारी नीतिगत भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है, जो किसी बड़ी जनक्रांति के बाद ही करवट लेगी।

जरा कल्पना कीजिए कि जब नरेंद्रमोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी मजदूर विरोधी परिस्थिति है तो पूर्व की सरकारों में कैसा जंगलराज रहा होगा, विचारणीय पहलू है। मजदूर शोषण कांड की एसआईटी और न्यायिक

नक्सलवाद या राजनीतिक हाथ बताया, जिससे सहमत होना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के हिंसक होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत भी नहीं हैं। वहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की 'पूंजीपति पक्षधर' नीति को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर शोषण का आरोप लगाया, जो अतिरेक है। चूंकि कांग्रेस और सपा ने सरकार की आलोचना की, इसलिए केंद्र भी सतर्क है।

इस अप्रत्याशित आंदोलन का प्रमुख निहितार्थ यह है कि यह आंदोलन श्रम नीतियों पर बहस तेज कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों से अंतरराज्यीय दबाव बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को मजदूर वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को कानून-व्यवस्था पर खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ी।

दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी।

यह कोरा सच है कि नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक-प्रशासनिक-राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है। नोएडा मजदूर आंदोलन 2027 यूपी विधानसभा चुनावों पर

जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम भारतीयों के भविष्य के साथ एफडीआई आकर्षित करने के चक्कर में घोर अन्याय हो रहा है, जिससे बचे जाने की जरूरत है।

अब नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं। चूंकि नोएडा में मजदूरों का हिंसक आंदोलन वेतन वृद्धि की मांग पर केंद्रित है, जो हरियाणा की 35% न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी से प्रेरित है। लिहाजा, योगी सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए। बताया गया कि यह प्रदर्शन फेज-2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूरे नोएडा में फैल गया, जहां पेशेवर विपक्षी आंदोलनों के तर्ज ओर तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने संवाद के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है और अविलंब इसके निर्णयों को लागू करने की जरूरत है।

जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की बात है तो योगी सरकार ने आंदोलन को साजिश,

अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह श्रमिक असंतोष को विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी ताजा घटना होने से विश्लेषण अनुमानित हैं, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इससे विपक्ष को लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की 'पूंजीपति नीति' बताकर मजदूरों का समर्थन किया, जो पीडीए (PDA) यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और विपक्षी एकता का संकेत दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक वोट (गौतमबुद्धनगर सीटें) प्रभावित हो सकते हैं।

इससे भाजपा की जमीनी चुनौती बढ़ेगी और हिंदुत्व दम तोड़ देगा, इसलिए योगी सरकार ने वेतन, ओवरटाइम सम्बन्धी निर्देश देकर क्षतिपूर्ति की कोशिश की, लेकिन इसे 'साजिश' बताकर विपक्ष को और हवा मिली। कानून-व्यवस्था का सवाल उठा, जो भाजपा के 'मजबूत सरकार' वाले नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे दिल्ली-एनसीआर में आंदोलन के फैलाव से पश्चिम यूपी की सीटें जोखिम में पड़ सकती हैं। वहीं, श्रम मुद्दा, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी से जुड़कर 2027 में प्रमुख हो सकता है, खासकर ग्रेटर नोएडा-जेवर जैसे क्षेत्रों में। इसलिए यदि समाधान न हुआ तो विपक्ष मजबूत, वरना भाजपा इसे 'विकास' के पक्ष में पलट सकती है। कुल मिलाकर, नोएडा रणभूमि बन चुका है।

दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी।

अब भारत में बढ़ी महंगाई की चुनौती

उम्मीद करें कि सरकार अमरीका-ईरान टकराव के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए और अधिक रणनीतिक कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। कच्चे तेल के लिए रूस और वेनेजुएला से आपूर्ति का रुख और बढ़ाया जाएगा। सरकार के द्वारा खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी सहित उर्वरकों की उपयुक्त आपूर्ति के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा आवश्यक होने पर मौद्रिक नीति सख्त करते हुए वर्तमान 5.25 प्रतिशत की नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को बढ़ाया जाएगा...

ब्रिज पंवार

यकीनन इस समय पश्चिमी एशिया में संघर्ष का असर भारत में महंगाई बढने के रूप में भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल ढुलाई के महंगा होने और तेल आपूर्ति बाधाओं के कारण दुनिया के साथ-साथ भारत में भी महंगाई बढ़ रही है। यद्यपि भारत में महंगाई अमरीका सहित दुनिया के अधिकांश देशों में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से बहुत कम है, लेकिन इस महंगाई का भारत की आर्थिकी और आम आदमी पर असर दिखाई देने लगा है। हाल ही में 13 अप्रैल को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर बढकर 3.4 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी में 3.21 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 3.11 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है। इसी प्रकार 15 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में थोक महंगाई दर बढकर 3.88 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। यह फरवरी माह में 2.13 प्रतिशत के स्तर पर थी। स्थिति यह है कि थोक मूल्य की यह महंगाई 38 महीने के उच्चतम स्तर पर है। निःसंदेह खाड़ी देशों से आयातित कच्चे माल के महंगे होने और ईंधन, बिजली व गैस की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरण आदि महंगे हुए हैं। खास तौर से आयातित पेट्रोकेमिकल से जुड़े कच्चा माल के महंगे होने से पेंट सहित विभिन्न उत्पादों की कीमतें अधिक बढ़ी हैं। साबुन, पेस्ट, बिस्किट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कई कंपनियां पैकेट छोटे करने

की रणनीति पर भी आगे बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, देश में महंगाई बढ़ने की एक नई चिंता यह भी है कि हाल ही में 13 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के कारण 2026 में सामान्य से कम मॉनसून का अनुमान लगाया है, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2023 के बाद पहली बार बारिश के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 92 प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। यह पूवार्नुमान 5 फीसदी अधिक या कम की मॉडल त्रुटि के साथ जारी किया गया है। यद्यपि पिछले आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मॉनसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव समान रहा तब खरीफ का उत्पादन कम नहीं हुआ, किन्तु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम हो सकती है। साथ ही दलहन और तिलहन का कम उत्पादन खाद्य मुद्रास्फीति पर असर डाल सकता है। ऐसे में महंगाई नियंत्रण के लिए राहत और सुधारों को तेजी से लागू करने की बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों व वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों में अमरीका और ईरान के बीच टकराव के लंबा खींचने पर भारत की विकास दर में कमी और महंगाई के बढ़ने के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध और ऊर्जा कीमतों व आपूर्ति बाधाओं के कारण भारत में विकास दर धीमी हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। मूडीज रेटिंग्स ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 6.8 प्रतिशत आंका गया था। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया, जो 2025-26 के 2.4 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में महंगाई दर के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से ऊपर जाना चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश के आम आदमी को युद्ध के संकट के बीच महंगाई से बचाने के मद्देनजर सरकार रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी है। इसके मद्देनजर पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखने के लिए उत्पाद कर में 10 रुपए प्रतिलीटर की कटौती किए की गई ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सकेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है। देश की सभी तेल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। सरकार के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही, पेट्रोल और डीजल की बाजार में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जा रही है। रोजाना करीब 50 लाख गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग 97 प्रतिशत है। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए डिलिवरी ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है।

दुनिया में तेजी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच भी देश में सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा सामान्य पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। वैश्विक तेल संकट को देखते हुए सरकार ने 11 अप्रैल को निर्यात किए जाने वाले डीजल और हवाई ईंधन (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क 34 रुपए बढ़ा दिया है ताकि देश में ईंधन की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें। सरकार ने महंगाई को नियंत्रित रखने तथा आम आदमी पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के मद्देनजर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए खाद्यान्न की रणनीतिक बिक्री करने और जरूरी आयात की सुविधा जैसे कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। निःसंदेह सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के लिए की गई विभिन्न आर्थिक और कूटनीतिक पहलों के लाभ मिले हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध से निर्मित महंगाई की चुनौती के बीच कुछ अहम बुनियादी बातें भारत के लिए महंगाई नियंत्रण की शक्ति बन गई हैं। इस समय भारत के पास विशाल खाद्यान्न भंडार और जरूरत की दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक आर्थिक अनुकूलताओं के रूप में दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में मार्च 2026 के अंत तक लगभग गेहूं और चावल का 600 लाख टन से अधिक का उपलब्ध स्टॉक खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की मजबूती है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, महंगाई की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास 10 अप्रैल तक 700 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा कोष की शक्ति भी है। उम्मीद करें कि सरकार अमरीका-ईरान टकराव के बीच महंगाई नियंत्रण के लिए और अधिक रणनीतिक कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। कच्चे तेल के लिए रूस और वेनेजुएला से आपूर्ति का रुख और बढ़ाया जाएगा। सरकार के द्वारा खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी सहित उर्वरकों की उपयुक्त आपूर्ति के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा आवश्यक होने पर मौद्रिक नीति सख्त करते हुए वर्तमान 5.25 प्रतिशत की नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) को बढ़ाया जाएगा। उम्मीद करें कि सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को कड़ाई से लागू करते हुए इसके तहत जरूरत के मुताबिक वस्तुओं के भंडारण की सीमा, नियमित छापेमारी और दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की राह पर भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी।

फांसी जैसी सजा से ही रुकेंगी पुलिस हिरासत में मौतें

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं।

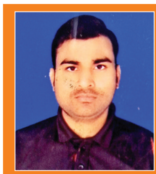

कपिल शर्मा

देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुमार्ना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन ज़िले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

इसी तरह लुधियाना जिले में करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई थी। मौत के मामले में लुधियाना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले

की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दीं। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी।

पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया है। जुलाई 2024 को मध्यप्रदेश के बिलाखेड़ी निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने 8 लाख रुपये की कथित चोरी के आरोप में उसे हिरासत में लिया था। हिरासत में मौत के बाद उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। इस जांच

के सिलसिले में एजेंसी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिरासत में हुई मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी फरार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है।कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की। जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा, ₹केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,630 हिरासत में मृत्युएँ दर्ज की गईं, जो देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों के 2023 के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, हिरासत में हुई मृत्युओं के संबंध में देश भर में केवल 345 मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं। एनएचआरसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 1996 और 2018 के बीच हिरासत में हुई 71% मौतें गरीब या कमजोर पृष्ठभूमि के बंदियों की थीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 के फैसले में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित किए थे। जिसके तहत रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी ज्ञापन रखना, चिकित्सा परीक्षण, कानूनी परामर्श, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य था। इन दिशा–निदेर्शों को अनुच्छेद 141 के अंतर्गत प्रवर्तनीय कानून माना जाता है। न्यायालय का यह आदेश कहीं धूल फांक रहा है। न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में गठित भारतीय विधि आयोग ने 30 अक्टूबर, 2017 को तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को सौंपी गई अपनी 273 वीं रिपोर्ट में केंद्र सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के यातना-विरोधी सम्मेलन की पुष्टि करने और यातना निवारण कानून लागू करने की सिफारिश की थी।

आयोग ने यातना निवारण के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस रिपोर्ट में यातना निवारण विधेयक के अलावा विधि आयोग ने यातना उन्मूलन के उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। रिपोर्ट में यातना के खतरे को कम करने और यातना के कृत्यों पर रोक लगाने और ऐसे कृत्यों के अपराधियों के लिए कठोर दंड की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट के साथ संलग्न विधेयक के मसौदे में आजीवन कारावास और जुमार्ने तक के दंड का प्रावधान था। आयोग ने न्यायसंगत मुआवजे का निर्णय न्यायालयों पर छोड़ दिया। इसके अलावा, आयोग ने यातना पीड़ितों, शिकायतकताओंं और यातना के मामलों के गवाहों को संभावित खतरों, हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी की गई थी।

1997 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की। इसकी पुष्टि करने का अर्थ यह होता कि भारत को यातना निवारण विधेयक पारित करना होगा, जिसे पहली बार 2010 में यूपीए द्वितीय सरकार द्वारा पेश किया गया था। इसमें किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक की सहमति से ऐसा कृत्य, जिससे गंभीर चोट पहुंचे या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को खतरा हो। इसमें जबरन कबूलनामा करवाने के उद्देश्य से, या धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, समुदाय या किसी अन्य आधार पर दंडित करने के लिए दी गई यातना के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रस्ताव था, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुमार्ना भी लगाया जा सकता है। विधेयक आज तक कानून नहीं बन पाया।

इससे साफ जाहिर है जो भी दल सत्ता में आता है, वह देश के मौजदा पुलिस सिस्टम में बदलाव नहीं करना चाहता। कारण साफ है यदि ऐसे कानून बन जाएंगे तो पुलिस अधिकारी नेताओं के इशारे पर नहीं नाचेंगे। जब नाचेंगे नहीं तो नेताओं के मौखिक तौर पर गैर कानूनी काम कैसे होंगे। यही वजह रही है कि केंद्र ने हाल ही में दंड संहिता को न्याय संहिता का नाम दे दिया है। इसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। पुलिस अफसरों को लापरवाही बरतने और सही तरीके से ड्यूटी को अंजाम नहीं देने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं किया गया। पुलिस हिरासत में मौतों का इस कानून में जिक्र तक नहीं किया गया। उल्टे पुलिस हिरासत में जब–जब मौतों का मामला सामने आता है, सरकार और पुलिस अफसर उसके रफा दफा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। सत्तारुढ राजनीतिक दलों की मिलीभगत का ही परिणाम है कि आज 21वीं सदी में भी भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें आदिम युग की याद दिलाती हैं।

लाल गलियारे का अंत: अमित शाह की नीति ने रची सुरक्षा की नई इबारत

अमित शाह ने बार-बार एक और महत्वपूर्ण बात कही है- 'संवाद और पुनर्वास'। उन्होंने उन युवाओं के लिए हमेशा 'लाल कालीन' बिछाई है जो गुमराह होकर हिंसा की राह पर चले गए थे। सरकार की आत्मसमर्पण नीति को इतना आकर्षक और सुलभ बनाया गया कि हजारों नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

अनादि शुक्ल

भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में यदि किसी एक समस्या ने दशकों तक देश की प्रगति को बाधित किया और हजारों निदोर्षों का लहू बहाया, तो वह नक्सलवाद था। एक समय ऐसा भी था जब तत्कालीन सरकारों ने इसे देश के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' स्वीकार किया था, लेकिन इसके समाधान के लिए वह ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई थी जो आज नजर आ रही है। आज जब हम 2026 के मुहाने पर खड़े हैं, तो भारत के नक्शे से 'लाल गलियारे' का सिकुड़ता दायरा और बस्तर के जंगलों में गूंजती शांति इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 'जीरो टॉलरेंस' नीति ने इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही नक्सलवाद को केवल एक स्थानीय कानून-व्यवस्था की समस्या मानने के बजाय इसे एक राष्ट्रव्यापी सुरक्षा चुनौती के रूप में चिन्हित किया और इसे समाप्त करने के लिए 'समाधान' और 'लौह प्रहार' जैसी रणनीतियों का सूत्रपात किया।

अमित शाह की कार्यशैली का सबसे प्रमुख पहलू उनका 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने विभिन्न भाषणों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि नक्सलवाद का अस्तित्व केवल बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि विकास की कमी और वैचारिक भ्रम के कारण टिका हुआ था। शाह ने उन 'अर्बन नक्सल' समूहों को भी बेनकाब

किया जो शहरों में बैठकर जंगलों में हिंसा फैलाने वालों के लिए वैचारिक कवच तैयार करते थे। गृह मंत्री का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और यदि कोई समूह हथियार उठाकर संविधान को चुनौती देता है, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना राज्य का उत्तरदायित्व है। इसी सोच के तहत उन्होंने सुरक्षा बलों को वह 'फ्री हैंड' दिया, जिसकी मांग वे दशकों से कर रहे थे। आज सुरक्षा बल न केवल नक्सलियों के गढ़ों में घुसकर प्रहार कर रहे हैं, बल्कि उन दुर्गम इलाकों में भी तिरंगा फहरा रहे हैं जहाँ पहले जाना असंभव माना जाता था।

पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में सैकड़ों नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों ने नक्सलियों की रसद, सूचना तंत्र और छिपने के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से इन क्षेत्रों का दौरा कर जवानों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और संचार के बेहतर साधनों से लैस किया।

गृह मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया था कि जब तक अंतिम नक्सली हथियार नहीं डाल देता या उसका सफाया नहीं हो जाता, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। अमित शाह की रणनीति केवल सैन्य कार्यवाही तक सीमित नहीं रही है। उनके भाषणों का एक बड़ा हिस्सा 'विकास' को समर्पित रहा है। उनका तर्क है कि जहाँ सड़क पहुँचती है, वहाँ नक्सलवाद पीछे हट जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सड़क संपर्क परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल उन इलाकों में बिछाया गया जहाँ कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। एकलव्य मॉडल स्कूलों के माध्यम से जनजातीय बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और मोबाइल टावरों के जरिए डिजिटल इंडिया को घने जंगलों तक पहुँचाना शाह के 'सर्वांगीण विकास' मॉडल का हिस्सा है। जब एक आदिवासी युवक के हाथ में बंदूक के बजाय स्मार्टफोन और रोजगार के अवसर आए, तो नक्सलियों की भर्ती प्रक्रिया स्वतः ही ध्वस्त हो गई।

अमित शाह ने बार-बार एक और महत्वपूर्ण बात कही है–'संवाद और पुनर्वास'। उन्होंने उन युवाओं के लिए हमेशा 'लाल कालीन' बिछाई है जो गुमराह होकर हिंसा की राह पर चले गए थे। सरकार की आत्मसमर्पण नीति को इतना आकर्षक और सुलभ बनाया गया कि हजारों नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

शाह ने अपने भाषणों में स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है जो भटक गए हैं, लेकिन जो निदोषों की हत्या और विकास कार्यों में बाधा डालेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों के लौह प्रहार का सामना करना पड़ेगा। यह 'कैरेट एंड स्टिक' (पुरस्कार और दंड) की नीति ही थी जिसने नक्सली संगठनों के भीतर दरार पैदा कर दी और उनके नेतृत्व को कमजोर कर दिया।

आज झारखंड का 'बूढ़ा पहाड़' हो या छत्तीसगढ़ का 'अबूझमाड़', इन क्षेत्रों की पहचान अब आतंक के बजाय प्रगति से होने लगी है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों और खुफिया एजेंसियों के बीच जिस तरह का समन्वय स्थापित किया, वह प्रशासनिक कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने 'यूनिफाइड कमांड' के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को तेज किया, जिससे ऑपरेशन की सटीकता बढ़ी और सुरक्षा बलों के हताहत होने की दर में भारी कमी आई।

अमित शाह का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में एक ऐसे सेनापति के रूप में देखा जाएगा जिसने देश की आंतरिक एकता को खंडित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल नक्सलियों को हराया है, बल्कि उन लाखों लोगों के मन में विश्वास जगाया है जो दशकों तक डर और अभाव के साये में जीने को मजबूर थे। आज का भारत अब 'लाल गलियारे' के अंत का जश्न मना रहा है और विकास के नए क्षितिज की ओर अग्रसर है, जहाँ गोलियों की जगह कलम होगी और भय की जगह स्वाभिमान होगा।

महिला कोटे से जुड़े संविधान बिल के लुढ़कने के सियासी निहितार्थ

हालांकि, सरकार ने शेष दो बिल (परिसीमन और अन्य) आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि वे मुख्य बिल पर निर्भर थे। एचएम अमित शाह और पीएम मोदी विपक्ष के विरोध को कांग्रेस के इतिहास से जोड़कर जनता में प्रचार करेंगे। यह 2029 चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज कर सकता है।

इंद्रेश शर्मा

इंडिया गठबंधन की विपक्षी एकजुटता ने पुनः सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से जुड़ा था, 16 अप्रैल 2026 को वोटिंग में गिर गया। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) की आवश्यकता थी, जो सरकार के रणनीतिकारों ने नहीं जुटा पाए। शायद पहली बार सदन में अमित शाह की रणनीति पिट गई। इसका राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि मोदी सरकार के लिए 12 साल में पहली बड़ी संवैधानिक हार हुई है, जो विपक्ष की एकजुटता को दशार्ता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे ₹संविधान पर हमला₹ बताकर कांग्रेस-विपक्ष की रणनीति की जीत घोषित की, जबकि भाजपा इसे विपक्ष विरोधी हथियार बनाने की योजना बना रही है। एक सत्ता विरोधी रणनीति के तहत जहां विपक्ष ने बिल को ₹छलावा₹ करार दिया, वहीं दावा किया कि यह परिसीमन और चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। वहीं, एक एनडीए नेता के अनुसार, बिल गिरने से सरकार अब सड़क पर विपक्ष को महिलाओं के अधिकारों के नाम पर घेरेगी। हालांकि, सरकार ने शेष दो बिल (परिसीमन और अन्य) आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि वे मुख्य बिल पर निर्भर थे। एचएम अमित शाह और पीएम मोदी विपक्ष के विरोध को कांग्रेस के इतिहास से जोड़कर जनता में प्रचार करेंगे। यह 2029 चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज कर सकता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का पुनः संदेश गया है। वहीं, मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने के लिए रणनीतिक बदलाव कर सकती है, खासकर 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हार के बाद। समझा जाता है कि

सरकार नई विधेयक रणनीति के तहत दो या तीन नए विधेयक ला सकती है: पहला लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेगा, जिसमें एससी/एसटी के लिए सब-कोटा भी शामिल होगा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं? दूसरा परिसीमन आयोग स्थापित करेगा, लेकिन इसे राज्यों के अनुमोदन से अलग रखा जा सकता है ताकि दो-तिहाई बहुमत आसान हो।

सरकार का मानना है कि विपक्ष से सहमति निर्माण के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी सभी दलों को पत्र लिखकर सर्वसम्मति की अपील कर चुके हैं, इसी सिलसिले में कांग्रेस और अन्य विपक्षियों से बातचीत जारी है। महिला कोटा बिल को 2029 चुनावों से पहले लागू करने के लिए 2011 जनगणना पर आधारित संशोधन पर जोर दिया, और नई जनगणना-परीक्षण का इंतजार खत्म किया जाएगा। इसके निमित्त संसदीय प्रक्रिया यह हैं कि विशेष सत्र बुलाकर संशोधित बिल पेश करना संभव होगा, जहां 18 घंटे लोकसभा और 10 घंटे राज्यसभा चर्चा होगी। वहीं सड़क पर प्रचार के साथ विपक्ष को ओबीसी हितों पर घेराव, जिससे राजनीतिक दबाव बनेगा।यह 2029 से पहले बहुमत जुटाने की कोशिश होगी।इस प्रकार देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को 2029 से पहले लागू करना संवैधानिक रूप से जटिल है, क्योंकि इसके लिए परिसीमन प्रक्रिया अनिवार्य है जो 2011 जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। इसका संभावित विकल्प संशोधित बिल पुनर्प्रस्तावहै जिसके तहत सरकार दोबारा संशोधित विधेयक ला सकती है, जिसमें लोकसभा सीटें बढ़ाकर (543 से 850 तक) 33% महिला कोटा सुनिश्चित हो, लेकिन विपक्ष सहमति के बिना दो-तिहाई बहुमत मुश्किल है। इसलिए विपक्ष से सर्वसम्मति की पहल तेज है।सरकार सभी दलों से बातचीत तेज कर विशेष सत्र बुलाना, परिसीमन को अलग रखकर बिल पास करवाना, हालांकि विपक्ष इसे ₹परिसीमन साजिश₹ मान रहा है।जहाँ तक व्यावहारिक बाधाओं की बात है तो परिसीमन आयोग को पब्लिक हियरिंग और प्रक्रिया में कम से कम 2-3 वर्ष लगते हैं, इसलिए 2029 चुनाव से पहले पूरा होना असंभव है। वहीं बिल गिरने से अब अगली जनगणना (2031) और उसके बाद के परिसीमन तक (2034+) देरी तय, दक्षिणी राज्यों की चिंताएं टल सकती हैं। सरकार सड़क प्रचार पर जोर देगी। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में गिरे महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर मुख्य रूप से परिसीमन प्रक्रिया, ओबीसी/एससी/एसटी सब-कोटा और राजनीतिक साजिश को लेकर आपत्तियां दर्ज कीं। मुख्य आपत्तियां निम्नलिखित हैं:-

पहला, परिसीमन साजिश: बिल को लोकसभा/विधानसभा सीटें बढ़ाने और 2011 जनगणना पर परिसीमन से जोड़ा गया, जिसे विपक्ष ने उत्तर भारत (विशेषकर भाजपा शासित राज्यों) को लाभ पहुंचाने वाली 'सीट रिबनिंग' करार दिया। फलतः दक्षिणी राज्य अपनी सीटें खोने के डर से विरोधी हो गए।

दूसरा, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुपस्थिति: 33% महिला कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सब-कोटा न होने से सामाजिक न्याय का उल्लंघन ठहराया, और इसे 'सवर्ण महिलाओं के लिए' नया मौका बताया।

तीसरा, संविधान पर हमला: राहुल गांधी ने इसे 'संविधान बचाओ' का मुद्दा बनाया, और दावा किया कि बिल चुनावी नक्शा बदलकर विपक्ष कमजोर करेगा। इस प्रकार राजनीतिक तर्क देते हुए विपक्ष ने इसे 'छलावा' कहा, क्योंकि लागू होने में 2029-34 तक देरी होगी। इसलिए एकजुट होकर वोटिंग में भाजपा नीत एनडीए को हराया।राजनीति

वहीं, मोदी सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया, जो 25-30 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। परिसीमन पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि परिसीमन 2011 जनगणना पर आधारित होगा, जो निष्पक्ष है और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा; यह सीट वृद्धि के साथ संतुलित होगा। अमित शाह ने चुनौती दी कि यदि विपक्ष संशोधन चाहे तो सदन एक घंटा रोकें, वे तुरंत बदलाव लाएंगे। वहीं, ओबीसी/एससी/एसटी कोटा पर जवाब देते हुए सरकार ने ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सब-कोटा की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने स्पष्ट कहा कि संविधान धर्म या जाति आधारित अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति नहीं देता; इसलिए मौजूदा एससी/एसटी कोटा में महिलाओं को प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष को 'महिलाओं के खिलाफ' करार दिया, और कहा कि पंचायत स्तर पर सफलता साबित हो चुकी है।

हालांकि राजनीतिक आरोपों का खंडन करते हुए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'संविधान पर हमला' सम्बन्धी दावे पर शाह ने कहा कि विपक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमत था लेकिन वोटिंग में नकारा; अब सड़क पर इसका जवाब मिलेगा। सभी दलों से सर्वसम्मति की अपील की गई।

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण बिल (संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026) के प्रमुख प्रावधान लोकसभा, और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़े हैं, जिसका मुख्य प्रावधान इस प्रकार है:-

पहला, आरक्षण का दायरा: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित, जिसमें एससी/एसटी आरक्षित सीटों का भी एक-तिहाई हिस्सा शामिल है।

दूसरा, परिसीमन प्रक्रिया: 2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का आवंटन और रोटेशन, जिसमें लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक प्रस्तावित है।

तीसरा, अवधि और प्रभावी तिथि: 15 वर्ष के लिए (संसद द्वारा विस्तार योग्य), अगले परिसीमन के बाद 2029 चुनावों से लागू होगा।

चौथा, अतिरिक्त विशेषताएं: रोटेशन आधारित सीटें प्रत्येक परिसीमन में बदलेंगी, लेकिन ओबीसी/ईडब्ल्यूएस सब-कोटा शामिल नहीं होना भी विवाद का कारण बना।

गाजियाबाद पुलिसिंग के 'त्रिनेत्र'

सुरक्षा, सेवा और सुशासन का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश के गेटवे कहे जाने वाले गाजियाबाद की पहचान कभी केवल 'इंडस्ट्रियल हब' के तौर पर थी, लेकिन आज यह 'सुरक्षित और स्मार्ट' सिटी की पहचान बना चुका है। इस बदलाव के पीछे उन तीन अधिकारियों की जुगलबंदी है, जिन्होंने खाकी को केवल पावर का प्रतीक नहीं, बल्कि 'विश्वास' का पर्याय बना दिया है। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़, एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी और एडिशनल सीपी राजकरण नैय्यर की यह त्रिमूर्ति आज गाजियाबाद में अपराधियों के लिए काल और आम नागरिक के लिए ढाल बनी हुई है।

HEADQUARTERS
POLICE COMMISSIONERATE
GHAZIABAD
जे. रविन्दर
J. RAVINDER
केशव कुमार चौधरी
KESHAV KUMAR CHOUDHARY
राज करन नय्यर
RAJ KARAN NAYYAR

खाकी का 'मानवीय' चेहरा और अनुशासन का 'मजबूत' स्तंभ, पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़

ललित कुमार

जब खाकी के साथ 'विद्वता' और 'विनम्रता' का मेल होता है, तो समाज में सुरक्षा का एक नया विश्वास जन्म लेता है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के वर्तमान सारथी आईपीएस जे. रविंदर गौड़ (2005 बैच) इसी विश्वास के जीते-जागते प्रतीक हैं। 1 दिसंबर 1973 को तेलंगाना की मिट्टी में जन्मे और 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में परास्नातक करने वाले रविंदर गौड़ ने अपनी कार्यशैली से यह सिद्ध कर दिया है कि पुलिसिंग केवल डंडे के दम पर नहीं, बल्कि 'संवाद' और 'सिस्टम' के दम पर चलती है।

गाजियाबाद में 'गौड़' युग, थानों में चाय और तमीज का 'नया दौर'

पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालते ही जे. रविंदर गौड़ ने जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया, वह था 'शिष्टाचार संवाद नीति'। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि थाने आने वाला हर फरियादी सम्मान का हकदार है। थानों में अब 'तू-तड़ाक' की जगह सम्मानजनक संबोधन ने ले ली है। फरियादियों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब फरियादी को कागज के लिए भटकना नहीं पड़ता, ऋक्षक की कॉपी सम्मान के साथ घर पहुंचाई जा रही है।

2,131 बीट, सुरक्षा का सूक्ष्म जाल

कमिश्नर गौड़ ने पूरे शहर को 2,131 बीट में बांटकर सुरक्षा को गली-मोहल्लों तक पहुंचा दिया है। अब हर सिपाही अपनी बीट का 'जिम्मेदार' है। गाजियाबाद की बढ़ती आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए उन्होंने 11 नए थानों का प्रस्ताव देकर भविष्य की सुरक्षित नींव रखी है। साहिबाबाद से लेकर राजनगर एक्सटेंशन तक, पुलिस की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाया जा रहा है।

क्यों खास है यह तिकड़ी?

आज गाजियाबाद की पुलिसिंग में जो सुधार दिख रहा है, वह किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि इन तीनों अधिकारियों की साझा सोच का नतीजा है।

कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने विभाग को एक 'विजन' और 'मानवीय चेहरा' दिया।

केशव कुमार चौधरी ने 'अनुशासन' और 'अपराधियों में खौफ' भरा।

राजकरण नैय्यर ने 'फील्ड पुलिसिंग' और 'त्वरित न्याय' को धरातल पर उतारा।

मिशन शक्ति और सामाजिक सरोकार

कमिश्नर गौड़ के नेतृत्व में 'मिशन शक्ति 0.5' ने गाजियाबाद की सड़कों पर एक नई ऊर्जा भरी है। जब पुलिस लाइन से सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली निकली, तो वह केवल एक मार्च नहीं था, बल्कि अपराधियों के लिए चेतावनी और महिलाओं के लिए सुरक्षा का संकल्प था। इसके अलावा, उनका विजन गाजियाबाद को एक 'स्मार्ट और क्लीन सिटी' बनाने का है, जिसमें वे प्लास्टिक मुक्ति और कचरा प्रबंधन (3R) पर जोर दे रहे हैं।

खाकी का 'संकल्प' और अपराधियों का 'काल'
एडिशनल सीपी केशव कुमार चौधरी

बिहार के दरभंगा की मिट्टी से उपजा एक 'हौसला' आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की सुरक्षा दीवार को मजबूती दे रहा है। आईपीएस केशव कुमार चौधरी (2009 बैच) केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज हैं जो

सीमित संसाधनों के बावजूद आसमान छूने का जज्बा रखते हैं।

यूपीएससी का सफर और संघर्ष

9 जनवरी 1981 को जन्मे केशव कुमार चौधरी का बचपन कलेक्ट्रेट की फाइलों और अनुशासन के बीच बीता। पिता कलेक्ट्रेट में कार्यरत थे, इसलिए प्रशासनिक गलियारों की सेवा और सम्मान को उन्होंने करीब से देखा था। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद, दूसरे प्रयास में 137वीं रैंक हासिल कर उन्होंने खाकी को चुना।

चित्रकूट से गाजियाबाद तक, बहादुरी का सफर

केशव कुमार चौधरी की कार्यशैली की चर्चा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में रही है। विशेषकर चित्रकूट में तैनाती के दौरान उन्होंने बीहड़ों में डकैतों के खिलाफ जो पराक्रम दिखाया, उसे आज भी याद किया जाता है। झांसी में डीआईजी और बहराइच में एसएसपी के रूप में उनके 'एक्शन' ने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी।

गाजियाबाद में 'स्मार्ट और सख्त' पुलिसिंग

एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में उन्होंने गाजियाबाद में 'इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग' पर जोर दिया है। उनके आने के बाद स्ट्रीट क्राइम में भारी गिरावट आई है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 2021 में डीजीपी सिल्वर डिस्क और 2024 में डीजीपी गोल्ड डिस्क से सम्मानित किया गया। वे मानते हैं कि 'सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही रणनीति और ईमानदारी से मिलती है।

गाजियाबाद के 'संकटमोचक' और फील्ड के खिलाड़ी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैय्यर

पुलिसिंग में एक कहावत है, 'शांति तब बनी रहती है जब कमांड की डोर एक सजग अधिकारी के हाथ में हो' गाजियाबाद में यह डोर राजकरण नैय्यर (2012 बैच) संभाल रहे हैं। नैय्यर की गिनती उत्तर प्रदेश कैडर के उन चुनिंदा अधिकारियों में होती है जो तकनीकी रूप से जितने दक्ष हैं, फील्ड में उतने ही सक्रिय।

कानून व्यवस्था के 'मैनेजमेंट गुरु'

राजकरण नैय्यर ने गाजियाबाद में कानून-व्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। इससे पहले वे अयोध्या और बलिया जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) रह चुके हैं। अयोध्या जैसी संवेदनशील जगह पर उन्होंने जिस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था और जन-सामंजस्य बनाए रखा, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में हुई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में नैय्यर ने गाजियाबाद की पुलिसिंग में 'क्विक रिस्पांस' पर फोकस किया है।

गाजियाबाद में नैय्यर का 'इम्पैक्ट'

अपराध नियंत्रण- इन्होंने हिस्ट्रीशीटर्स और पेशेवर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष डेटाबेस तैयार करवाया है।

ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन- शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए इन्होंने तकनीकी समाधान और पुलिस की सड़कों पर विजिबिलिटी को बढ़ाया।

क्राइम सीन मॉनिटरिंग- नैय्यर खुद अक्सर देर रात तक सड़कों पर गश्त करते देखे जाते हैं, जिससे बल के मनोबल में वृद्धि हुई है।

संवाद और समाधान

राजकरण नैय्यर की सबसे बड़ी खूबी उनका 'जन-सुनवाई' का तरीका है। वे फरियादियों की बात को गहराई से सुनते हैं और मौके पर ही समाधान निकालने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पुलिस और पब्लिक के बीच उस 'दीवार' को गिरा दिया है जो अक्सर न्याय के बीच में आती थी।

इन तीनों अधिकारियों की कार्यशैली का ही परिणाम है कि आज गाजियाबाद का व्यापारी बेखौफ व्यापार कर रहा है, महिलाएं देर रात तक सुरक्षित महसूस कर रही हैं और पुलिस विभाग का हर सिपाही गर्व से ड्यूटी कर रहा है। गाजियाबाद केवल दिल्ली का पड़ोसी जिला नहीं है, बल्कि यह 'हाई-टेक और संवेदनशील पुलिसिंग' का मॉडल बन चुका है, सावधानी और शौर्य का यह संगम गाजियाबाद के इतिहास में 'स्वर्णिम अक्षरों' में दर्ज होगा।

सुरक्षा का माध्यम बने मुनाफे का जाल नहीं

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, हजारों करोड़ रुपये के बीमा दावे हर वर्ष खारिज कर दिए जाते हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि बीमा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। अक्सर देखा गया है कि पॉलिसी लेते समय ग्राहकों को शर्तों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती।

अजीत शर्मा

बीमा का मूल उद्देश्य जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करना है। यह व्यवस्था व्यक्ति को बीमारी, दुर्घटना या अन्य संकटों के समय आर्थिक सहारा देती है। परंतु आज के दौर में यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में जो जटिलताएं, अपारदर्शिता और मनमानी देखने को मिल रही है, उसने आमजन के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। बीमा, जो सुरक्षा का माध्यम होना चाहिए था, वह कई बार शोषण का उपकरण बनता जा रहा है। वर्तमान समय में चिकित्सा सेवाओं की लागत अत्यधिक बढ़ चुकी है। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च लाखों में पहुंच जाता है। सरकार के द्वारा रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराई भूमि पर बने अस्पताल आज गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा एक आवश्यक सुरक्षा कवच के रूप में उभरता है। बीमा कंपनियां भी इसी भय और भविष्य की अनिश्चितता का उपयोग कर लोगों को पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन वास्तविक समस्या तब सामने

आती है जब बीमा धारक को उसकी जरूरत होती है। दावों के निपटान के समय कंपनियां अनेक तकनीकी कारणों, शर्तों और अपवादों का हवाला देकर भुगतान से बचने का प्रयास करती हैं।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, हजारों करोड़ रुपये के बीमा दावे हर वर्ष खारिज कर दिए जाते हैं। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि बीमा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। अक्सर देखा गया है कि पॉलिसी लेते समय ग्राहकों को शर्तों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। जटिल भाषा में लिखे गए नियम और शर्तें आम व्यक्ति की समझ से बाहर होती हैं। परिणामस्वरूप, जब दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हीं शर्तों को आधार बनाकर भुगतान रोक दिया जाता है। इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच संभावित गठजोड़ भी है। कई मामलों में अस्पताल अत्यधिक बिलिंग करते हैं और बीमा कंपनियां कम भुगतान करती हैं, जिससे मरीज को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। कई बार तो ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जहां अस्पताल बकाया राशि के कारण मरीज के शव को तक रोक लेते हैं, जो मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है।

यदि हम विकसित देशों की तुलना करें, तो वहां बीमा प्रणाली अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी है। दावों का निपटान समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से किया जाता है। भारत में भी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) जैसे नियामक संस्थान मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित और संतुलित करना है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते रहे हैं। नियामक तंत्र की निष्क्रियता या सीमित हस्तक्षेप के कारण बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस स्थिति में सुधार के लिए सबसे पहले बीमा प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। पॉलिसी दस्तावेजों को आम भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उसकी शर्तों को समझ सके। इसके साथ ही, बीमा एजेंटों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वे ग्राहकों को पूरी और सही जानकारी दें। गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है- दावा निपटान प्रक्रिया का सरलीकरण। बीमा दावों के लिए एक मानकीकृत और समयबद्ध प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। यदि कोई दावा खारिज किया जाता है, तो उसके स्पष्ट और उचित कारण बताए जाएं। इसके लिए एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र भी होना चाहिए, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उसे त्वरित न्याय मिल सके। तीसरा, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उपचार की लागत को नियंत्रित करने के लिए एक मानक दर प्रणाली लागू की जा सकती है। इससे अनावश्यक बिलिंग और वित्तीय शोषण पर रोक लगेगी। साथ ही, कैशलेस उपचार की सुविधा को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि मरीज को तत्काल आर्थिक राहत मिल सके। चौथा, सरकार को इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जो बीमा कंपनियों और अस्पतालों की गतिविधियों पर नजर रखे। समय-समय पर ऑडिट और जांच के माध्यम से अनियमितताओं को उजागर किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पांचवां, बीमा साक्षरता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बीमा की शर्तों, अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। विशेष रूप से गरीब और अशिक्षित वर्ग के लिए सरल मार्गदर्शिका और सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर बीमा व्यवसाय को केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। जब तक इस क्षेत्र में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक आमजन का विश्वास बहाल नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि बीमा प्रणाली को पुनर्गठित कर उसे जनहितकारी बनाया जाए। सरल प्रक्रियाएं, स्पष्ट नियम, सशक्त नियामक तंत्र और जागरूक उपभोक्ता-ये चार स्तंभ ही बीमा क्षेत्र को उसकी वास्तविक दिशा में ले जा सकते हैं। यदि समय रहते इन सुधारों को लागू नहीं किया गया, तो बीमा का यह महत्वपूर्ण साधन आम आदमी के लिए सुरक्षा के बजाय संकट का कारण बना रहेगा।

चिकित्सा और बीमा-दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलतः मानव जीवन की सुरक्षा, राहत और सेवा से जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज ये दोनों क्षेत्र आमजन के लिए सबसे अधिक जटिल, महंगे और अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। एक ओर रियायती जमीन पर बने निजी अस्पताल गरीबों को मुफ्त इलाज देने के अपने दायित्व से बचते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य बीमा के नाम पर बीमा कंपनियां ऐसी शर्तें और प्रक्रियाएं थोप देती हैं कि जरूरत के समय मरीज को बीमा का लाभ मिलना कठिन हो जाता है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संवेदनहीन व्यवस्था का प्रतीक बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के रियायती जमीन पर बने अस्पतालों को नोटिस जारी करना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने जैसा है। जब अस्पताल रियायती जमीन लेते समय गरीबों के इलाज का वायदा करते हैं, तो वह केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व होता है।

बिहार पंचायत चुनावः पहली बार ईवीएम से होगा मतदान

बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर 2026 से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराए जाएंगे। अब तक राज्य में पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं।

निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए एम-3 (M3) मॉडल की ईवीएम यूनिट खरीदने की तैयारी में है, जिसे एम-2 (M2) मॉडल से अधिक उन्नत माना जाता है। आयोग करीब 32 हजार से अधिक ईवीएम यूनिट खरीदने जा रहा है। इन मशीनों की खासियत यह है कि इनमें 24

सचिन तोमर

बैलेट यूनिट तक जोड़ी जा सकती हैं और एक साथ 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। मतदान के दौरान एक कंट्रोल यूनिट के साथ छह पदों के लिए छह बैलेट यूनिट आसानी से जोड़ी जा सकती हैं।

इन ईवीएम मशीनों की खरीद पर करीब 64 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, राज्य सरकार पहले ही पंचायत चुनाव के आयोजन के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दे चुकी है।

कम हो सकते हैं चुनाव के चरण

ईवीएम के इस्तेमाल से इस बार पंचायत चुनाव के चरणों की संख्या कम होने की संभावना है। वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराए गए थे, जो 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चले थे। इसके अलावा इस बार विधानसभा चुनाव की तर्ज पर सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।

नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर होगा चुनाव

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराए जाएंगे। बिहार पंचायती

इन मशीनों की खासियत यह है कि इनमें 24 बैलेट यूनिट तक जोड़ी जा सकती हैं और एक साथ 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। मतदान के दौरान एक कंट्रोल यूनिट के साथ छह पदों के लिए छह बैलेट यूनिट आसानी से जोड़ी जा सकती हैं।

राज अधिनियम की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत आरक्षण रोस्टर प्रत्येक दो क्रमिक चुनावों के बाद बदला जाता है। वर्ष 2016 और 2021 के चुनावों में पुराना रोस्टर लागू रहा था, इसलिए 2026 के चुनाव में नया रोस्टर प्रभावी होगा। हालांकि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पदों का आरक्षण जिला अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

सभी वर्गों को मिलेगा नेतृत्व का अवसर

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक कुमार के अनुसार मौजूदा आरक्षण रोस्टर के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसमें बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए रोस्टर से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व का अवसर मिलेगा।

जहां पहले सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि चुने जाते थे, वहां अब आरक्षित वर्ग को मौका मिल सकता है, जबकि जिन क्षेत्रों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा है वहां सामान्य वर्ग को अवसर मिल सकता है। आरक्षण का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।

इस बार भी पुराने परिसीमन पर होगा चुनाव

काफी समय से पंचायत चुनाव में नए परिसीमन लागू करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन 2021 की जनगणना पूरी नहीं होने के कारण इस बार भी पंचायत चुनाव लगभग 30 वर्ष पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा लगातार नए परिसीमन की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि समय के साथ क्षेत्रों की आबादी बदलती रहती है, इसलिए कुछ वर्षों के अंतराल पर परिसीमन जरूरी है। यदि किसी पंचायत की आबादी अधिक हो जाती है तो परिसीमन के आधार पर नई पंचायत का गठन किया जाना चाहिए।

कुल 2.55 लाख पदों के लिए होंगे चुनाव

बिहार में इस बार पंचायत चुनाव कुल 2,55,379 पदों के लिए कराए जाएंगे। इनमें पंच और वार्ड सदस्य के 1,13,307-1,13,307 पद, मुखिया और ग्राम कचहरी सरपंच के 8,053-8,053 पद, जिला परिषद सदस्य के 1,162 पद तथा पंचायत समिति सदस्य के 11,497 पद शामिल हैं।

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

मार्केट क्रैश: 10 साल के 5 बड़े झटके

एन के शर्मा

भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाजार पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। पिछले एक दशक में कई आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक घटनाओं ने बाजार को अचानक झटका दिया। इन घटनाओं के कारण निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बाजार में घबराहट भरी बिकवाली देखने को मिली। हालांकि इन बड़े झटकों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने लंबी अवधि में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले दस वर्षों में निफ्टी 50ने लगभग 68 प्रतिशत और सेंसेक्स ने करीब 195 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों को मजबूत लाभ पहुंचाया है।

नीचे पिछले दस वर्षों की ऐसी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जब भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई।

नोटबंदी 2016: बाजार में दहशत भरी बिकवाली

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद अगले दिन बाजार में भारी घबराहट देखने को मिली। 9 नवंबर को बाजार खुलते ही निवेशकों ने बड़े पैमाने पर शेयर बेचने शुरू कर दिए।

इसी दौरान अमेरिका में चुनावी परिणामों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के शुरूआती संकेतों ने वैश्विक बाजारों में भी अस्थिरता पैदा कर दी।

इस गिरावट में सेंसेक्स लगभग 1,689 अंक (6.12%) गिरकर 26,902 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 541 अंक (6.33%) गिरकर

8,002पर पहुंच गया। इस दौरान रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जबकि सोने की कीमतों में तेज उछाल आया।

कोविड-19 लॉकडाउन 2020: इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में एक

कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 23 मार्च 2020 को भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। इस दिन सेंसेक्स 3,935 अंक (13.15%)गिर गया, जबकि निफ्टी 50 1,135 अंक (12.98%) टूट गया।

जनवरी 2020 में बाजार अपने उच्च स्तर पर था, लेकिन मार्च तक बाजार अपने मूल्य का लगभग 38 प्रतिशत खो चुका था। वैश्विक महामारी के कारण यह घटना हाल के वर्षों के सबसे गंभीर बाजार संकटों में गिनी जाती है।

हिंडनबर्ग-अदाणी संकट 2023

जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर Hindenburg Research की रिपोर्ट ने Adani Group पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग अनियमितताओं के आरोप लगाए।

रिपोर्ट सामने आने के बाद अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई और कुछ ही हफ्तों में समूह की कंपनियों का बाजार मूल्य100 अरब डॉलर से अधिक कम हो गया। हालांकि इस घटना का असर पूरे बाजार पर कोविड-19 जैसी व्यापक गिरावट के रूप में नहीं देखा गया।

2024 लोकसभा चुनाव परिणाम दिवस

4 जून 2024 कोभारत लोकसभा चुनाव 2024 परिणामके दौरान भी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरूआती रुझानों में सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने के संकेतों से निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई।

इस दौरान सेंसेक्स 3,700 अंक से अधिकगिरकर 72,079 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 900 अंक टूटकर 21,884 पर पहुंच गया। यह पिछले चार वर्षों की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी।

अमेरिका-ईरान तनाव 2026: तेल कीमतों से बाजार में उथल-पुथल

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया। कच्चे तेल की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने से भारतीय बाजार में भारी दबाव देखा गया।

इस घटनाक्रम के दौरान सेंसेक्स लगभग 2,500 अंक से अधिक गिरकर 76,424तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब750 अंक गिरकर 23,697पर आ गया। इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर विमानन और पेंट कंपनियों के शेयरों में देखा गया, क्योंकि इन क्षेत्रों की लागत कच्चे तेल की कीमतों से सीधे प्रभावित होती है।

निष्कर्ष

पिछले दस वर्षों में भारतीय शेयर बाजार ने कई बड़े झटके देखे हैं-चाहे वह आर्थिक फैसले हों, वैश्विक महामारी, कॉर्पोरेट विवाद या भू-राजनीतिक तनाव। इन घटनाओं ने अल्पकाल में बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन दीर्घकाल में भारतीय बाजार ने मजबूती दिखाई है। यही कारण है कि विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह देते हैं कि बाजार की अस्थिरता से घबराने के बजाय दीर्घकालिक निवेश रणनीति अपनानी चाहिए।

सपना था IAS बनने का... IPS बनने के बाद भी नहीं रुकी आस्था जैन, UPSC में हासिल की AIR-9

मेहनत, धैर्य और फोकस की कहानी

अरुण शर्मा

सपने अक्सर सब्र मांगते हैं और कभी-कभी वे सबसे अप्रत्याशित पलों में पूरे होते हैं।

उत्तर प्रदेश के शामली की बेटी आस्था जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने UPSC Civil Services Examination में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR)-9 हासिल की है। खास बात यह है कि जब उनका रिजल्ट आया, उस समय वह Indian Police Service की ट्रेनिंग कर रही थीं।

आस्था का सपना हमेशा से IAS अधिकारी बनने का था, जो अब उनकी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बाद पूरा हो गया।

शामली की रहने वाली, पिता हैं छोटे व्यापारी

आस्था जैन उत्तर प्रदेश के Shamli जिले के कांधला क्षेत्र की निवासी हैं। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज और मेहनती रही हैं।

उनके पिता अजय जैन एक छोटे व्यापारी हैं और किराना व कंफेक्शनरी की दुकान चलाते हैं। बेटी की इस बड़ी उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। उनके जिले और इलाके के लोग भी आस्था की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, वहीं से शुरू की UPSC की तैयारी

आस्था जैन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई University of Delhi से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कोचिंग के साथ-साथ खुद से भी लगातार पढ़ाई की और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का भी सहारा लिया। उनके पिता के अनुसार, आस्था शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे देश में चौथी रैंक हासिल की थी।

IPS ट्रेनिंग के दौरान मिला IAS बनने का मौका

हालांकि आस्था का सपना शुरू से ही IAS अधिकारी बनने का था, इसलिए उन्होंने IPS चयन के बाद भी अपनी तैयारी जारी रखी। लगातार मेहनत और धैर्य के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी सफलता मिली और उन्होंने वढरउ 2025 के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक-9 हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया।

पहले भी पास कर चुकी थीं UPSC

आस्था जैन इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 131 प्राप्त की थी। इसके बाद उनका चयन IPS अधिकारी के रूप में हुआ। उन्हें राजस्थान कैडर मिला और फिलहाल वह Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही हैं।

परिवार को दिया सफलता का श्रेय

आस्था जैन अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और भाई-बहनों को देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, धैर्य और सही लक्ष्य के साथ कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है।

मैरिटल रेप पर कानून की खामोशी: क्या विवाहित महिलाओं के साथ नाइंसाफी?

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने एक बार फिर मैरिटल रेप (वैवाहिक दुष्कर्म) को लेकर देशभर में बहस तेज कर दी है।

अदालत ने वैवाहिक संबंध के भीतर 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के आरोप को अपराध मानने से इनकार करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में ऐसे मामलों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने कानून में मौजूद उस अपवाद को केंद्र में ला दिया है, जो पति को विशेष संरक्षण देता है।

भारत में दुष्कर्म की परिभाषा समय के साथ विस्तृत हुई है। 2013 के संशोधन और निर्भया कांड के बाद कानून में कई बदलाव किए गए, जिनमें अप्राकृतिक कृत्यों को भी दुष्कर्म की श्रेणी में शामिल किया गया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा विरोधाभास भी बना रहा—अगर यही कृत्य पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाए, तो उसे अपराध नहीं माना जाता। यही अपवाद आज सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। मौजूदा कानून के अनुसार, यदि पत्नी बालिग है, तो उसकी असहमति के बावजूद पति द्वारा बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाता। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है—क्या शादी के बाद महिला की 'सहमति' का कोई महत्व नहीं रह जाता? क्या वैवाहिक संबंध महिला के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर है?

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए 15 से 18 वर्ष की नाबालिग पत्नी के साथ जबरन संबंध को दुष्कर्म माना था, लेकिन बालिग विवाहित महिलाओं के मामले में अब भी कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है। नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) में दुष्कर्म की परिभाषा को और व्यापक किया गया है, फिर भी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

इसका परिणाम यह है कि जहां अविवाहित महिलाओं और नाबालिगों को कानून अधिक सुरक्षा देता है, वहीं विवाहित महिलाओं के अधिकार सीमित नजर आते हैं। कई मामलों में यह स्थिति महिलाओं को न्याय से वंचित कर सकती है और शोषण का खतरा बढ़ा सकती है।

सरकार का तर्क है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से वैवाहिक संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके सामाजिक- कानूनी दुष्परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया है कि पत्नी की सहमति का उल्लंघन पति का अधिकार नहीं हो सकता।

फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां इस पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद है। यह फैसला न केवल कानून की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि भारत में विवाह के भीतर महिला की सहमति और सम्मान को कितनी अहमियत दी जाती है।

अंततः सवाल यही है—क्या कानून का उद्देश्य केवल संस्था की रक्षा करना है या उसमें जुड़े व्यक्तियों के अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा करना? जब तक इस सवाल का संतुलित जवाब नहीं मिलता, तब तक मैरिटल रेप पर बहस जारी रहेगी।

मनोज शर्मा

इन 2 चीजों के नाम पर फीस नहीं मांग सकते स्कूल

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS एडमिशन प्रक्रिया शुरू

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। Directorate of Education Delh ने शैक्षणिक सत्र 2026-27के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा-1 में EWS/DG/CWSN कैटेगरीके तहत दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।

अभिभावक EWS Admissions Delhi Portal या EduDel Portal पर जाकर16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनकर सकते हैं।एडमिशन से पहले अभिभावकों को फीस से जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है।

गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं

दिल्ली के निजी स्कूलों में कुल सीटों में से25 प्रतिशत सीटें EWS/DG/CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

- 75% सीटेंसामान्य (ओपन) कैटेगरी के लिए
- 25% सीटें EWS/DG/CWSN कैटेगरी के लिए

इन 25 प्रतिशत सीटों में भी अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय है:

- 22% सीटें EWS और DG कैटेगरी के लिए
- 3% सीटें CWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के लिए

इन दो चीजों के नाम पर फीस नहीं मांग सकते स्कूल

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निदेर्शो के अनुसार निजी स्कूलदो प्रकार की फीस नहीं ले सकते:

1. कैपिटेशन फीस

कैपिटेशन फीस वह अतिरिक्त शुल्क होता है जो स्कूल द्वारा तय फीस के अलावा किसी भी रूप में दान या भुगतान के तौर पर लिया जाता है।

2. डोनेशन फीस

एडमिशन के नाम पर किसी भी प्रकार का डोनेशन लेना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।

नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

Right to Education Act 2009 की धारा 13(1) और दिल्ली

हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार कोई भी स्कूल एडमिशन के समय कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं ले सकता। अगर कोई स्कूल यह नियम तोड़ता है तो उस पर लीगई फीस का 10 गुना तक जुमार्ना लगाया जा सकता है।

EWS एडमिशन के लिए आय सीमा

एहर कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए माता-पिता कीसभी स्रोतों से सालाना आय 5 लाख रुपये से कमहोनी चाहिए।

- आय प्रमाण पत्रदिल्ली सरकार के राजस्व विभागद्वारा जारी होना चाहिए।
- प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना जरूरी है।

किन बच्चों को मिलता है DG कैटेगरी में एडमिशन

वंचित वर्ग (DG) में कई विशेष श्रेणियां शामिल हैं :

- एससी / एसटी
- ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)
- अनाथ बच्चे
- ट्रांसजेंडर बच्चे
- एचआईवी से प्रभावित या पीड़ित बच्चे

इन बच्चों के लिए संबंधित कैटेगरी सर्टिफिकेटजरूरी होता है।

CWSN कैटेगरी के लिए जरूरी दस्तावेज

CWSN (Children With Special Needs) कैटेगरी में एडमिशन के लिएसरकारी अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रहोना आवश्यक है। इस कैटेगरी में माता-पिता के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होता।

EWS नर्सरी एडमिशन 2026: उम्र सीमा

अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा EWS, DG या CWSN कैटेगरी के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करता हो।

कक्षा के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार है:

- **नर्सरी:** 3 से 5 वर्ष
- **केजी:** 4 से 6 वर्ष
- **कक्षा 1:** 5 से 7 वर्ष

पेरेंट्स के लिए जरूरी सलाह

- आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।
- केवल सरकारी वेबसाइट पर ही आवेदन करें।
- एडमिशन के नाम पर किसी भी अतिरिक्त फीस या डोनेशन की मांग होने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

भविष्य की सवारी: फ्लाइंग टैक्सी

संजय बैंसला

भारत में शहरी परिवहन के भविष्य को नई दिशा देने वाली तकनीक अब वास्तविकता के करीब पहुंच रही है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप The ePlane Company देश की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी e200x पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में एडवांस्ड सिमुलेशन और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विकास प्रक्रिया को तेज और सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाया जा सके।

इस परियोजना में एयर टैक्सी का एक अत्यंत सटीकडिजिटल ट्विनतैयार किया गया है, जिसे NVIDIA के ओम्नीवर्स प्लेटफॉर्मपर विकसित किया गया है। यह वर्चुअल मॉडल इंजीनियरों को वास्तविक उड़ान से पहले फ्लाइट डायनामिक्स, सेंसर सिस्टम और आपातकालीन परिस्थितियों का परीक्षण डिजिटल वातावरण में करने की सुविधा देता है।

डिजिटल ट्विन की मदद से इंजीनियर लाखों किलोमीटर की वर्चुअल उड़ानों का डेटा एकत्र करेंगे। इससे शहरी हवाई परिवहन को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और कुशल बनाने में मदद मिलेगी और वास्तविक उड़ान के दौरान जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

एयर टैक्सी मेंएनवीडिया के ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टमभी लगाए जाएंगे। ये सिस्टम कैमरों और रडार से आने वाले डेटा को रियल-टाइम में प्रोसेस करेंगे, जिससे उड़ान के दौरान तेजी से और सटीक निर्णय लिए जा सकेंगे। इससे ऑपरेशनल सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होगा। एविएशन और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का यह संयोजन आधुनिक विमानन उद्योग में तेजी से महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जटिल सिमुलेशन को वास्तविक दुनिया जैसी परिस्थितियों में दोहराने के लिए शक्तिशाली जीपीयू आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है।

परीक्षण के अलावा, डिजिटल ट्विन कोप्रीडिक्टिव मेंटेनेंस टूलके रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह विमान के विभिन्न कंपोनेंट्स की डिजिटल नकल तैयार कर संभावित तकनीकी समस्याओं का पहले ही पता लगाने में मदद करेगा, जिससे ऑपरेशनल जोखिम कम होंगे। द ईप्लेन कंपनी में एवियोनिक्स सिस्टम्स और ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल इंजीनियर बकथकोलाहलन श्यामसुंदर के अनुसार, वर्चुअल टेस्टिंग वातावरण विमान को वास्तविक तैनाती से पहले सीखने और बेहतर बनने का अवसर देता है। इससे इंजीनियर दुर्लभ परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं, एल्गोरिद्म को बेहतर बना सकते हैं और सुरक्षा मानकों को डिजिटल स्तर पर परख सकते हैं।

यह प्रोजेक्ट भारत के उभरतेअर्बन एयर मोबिलिटीसेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह दर्शाता है कि भारत भविष्य की एविएशन तकनीकों को देश में ही विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पायलट कैसे बनें? योग्यता, खर्च और सैलरी की पूरी जानकारी

रवि जैन

पायलट बनना युवाओं के लिए एक ड्रीम करियर माना जाता है, लेकिन इसके लिए सही योग्यता, कड़ी ट्रेनिंग और बड़ा निवेश जरूरी होता है। भारत में पायलट बनने के लिए सबसे पहले 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स के साथ कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसे ओपन बोर्ड के जरिए फिजिक्स और मैथ्स पास करना होता है।

इसके बाद उम्मीदवार को DGCA (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) द्वारा मान्यता प्राप्त Class 2 और Class 1 मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है। इसके बाद CPL (Commercial Pilot License) के लिए आवेदन किया जाता है।

CPL पाने के लिए DGCA की लिखित परीक्षाएं पास करनी होती हैं, जिनमें नेविगेशन, मौसम विज्ञान, एयर रेगुलेशन और टेक्निकल विषय शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में कम से कम 70% अंक जरूरी होते हैं। इसके बाद उम्मीदवार को DGCA से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) से 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी करनी होती है।

ट्रेनिंग का खर्च इस करियर का सबसे अहम पहलू है। भारत में उढछ ट्रेनिंग पर करीब 50 से 55 लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि विदेशों में यह 35 से 60 लाख रुपये तक हो सकता है। वहीं एयरलाइन कैडेट पायलट प्रोग्राम के जरिए यह खर्च 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकता है।

करियर की शुरूआत फर्स्ट ऑफिसर (को-पायलट) के रूप में होती है, जहां सैलरी लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपये प्रति माह होती है। अनुभव बढ़ने और 1500 घंटे की फ्लाइंग पूरी करने के बाद ATPL लाइसेंस लेकर कैप्टन बना जा सकता है, जहां सैलरी 4 से 8 लाख रुपये प्रति माह या उससे अधिक हो जाती है।

कुल मिलाकर, पायलट बनना चुनौतीपूर्ण और महंगा जरूर है, लेकिन इसमें करियर ग्रोथ, सम्मान और आकर्षक आय की अपार संभावनाएं हैं।

बदलती सोच के दौर में युवाओं का नया लाइफस्टाइल ट्रेंड

अनिल वशिष्ठ

परंपरागत रूप से भारतीय समाज में शादी और परिवार बसाना जीवन का एक जरूरी कदम माना जाता रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ युवाओं की सोच में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज की पीढ़ी में एक नया ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसे 'सिंगल बाय च्वाइस' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग जानबूझकर शादी न करने और अकेले रहने का फैसला लेते हैं।

बॉलीवुड में भी दिखता है यह ट्रेंड

मनोरंजन जगत में भी कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने लंबे समय से सिंगल रहने का विकल्प चुना है। इनमें Salman Khan, Tabu, Tusshar Kapoor और Ekta Kapoor जैसे नाम शामिल हैं। इन हस्तियों ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हुए शादी न करने का निर्णय लिया है।

क्यों बढ़ रहा है kSingle By Choicel ट्रेंड

1. करियर पर ज्यादा फोकस

आज के समय में कई युवा अपने करियर और पेशेवर विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि शादी और रिश्तों की जिम्मेदारियां कभी-कभी उनके लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं में बाधा बन सकती हैं। इसलिए वे पहले अपने करियर को मजबूत करना चाहते हैं।

2. व्यक्तिगत आजादी की चाह

नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देती है। सिंगल रहने से उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिलती है। वे अपने समय, लाइफस्टाइल और शौक के अनुसार जीवन जी सकते हैं।

3. आर्थिक आत्मनिर्भरता

पहले के समय में शादी को आर्थिक सुरक्षा से भी जोड़ा जाता था। लेकिन आज कई युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। नौकरी और व्यवसाय के माध्यम से वे खुद अपने जीवन की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, इसलिए वे शादी को अनिवार्य नहीं मानते।

सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने भी रिश्तों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। आज युवाओं को दुनिया भर के नए अनुभव और अवसर मिलते हैं। इस वैश्विक Exposure के कारण पारंपरिक रिश्तों को लेकर सोच में बदलाव आ रहा है।

4. बदलता डिजिटल लाइफस्टाइल

सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने भी रिश्तों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। आज युवाओं को दुनिया भर के नए अनुभव और अवसर मिलते हैं। इस वैश्विक exposure के कारण पारंपरिक रिश्तों को लेकर सोच में बदलाव आ रहा है।

5. रिश्तों के प्रति बदली सोच

आज कई युवा मानते हैं कि शादी तभी करनी चाहिए जब व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए वे सामाजिक दबाव में आकर जल्दबाजी में शादी करने के बजाय सही समय का इंतजार करना पसंद करते हैं।

समाज पर पड़ सकता है असर

kSingle By Choicel ट्रेंड के बढ़ने से समाज में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

- शादी की औसत उम्र बढ़ सकती है।
- छोटे परिवारों का चलन बढ़ सकता है।
- व्यक्तिगत जीवनशैली और स्वतंत्रता को अधिक महत्व मिल सकता है।

बदलती सोच का संकेत

हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस ट्रेंड को अपनाए, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि समाज में रिश्तों और जीवन के फैसलों को लेकर सोच बदल रही है। आज के समय में लोग अपनी खुशी, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन के महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं।

आस्था की नगरी वाराणसी धार्मिक महत्व

वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के प्राचीनतम जीवित नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर और हर गली एक कथा कहती है। यह नगरी मानव जीवन के आरंभ से अंत तक की यात्रा का साक्षी है—जन्म से लेकर मोक्ष तक।

जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को समझना चाहता है, उसे वाराणसी अवश्य जाना चाहिए। यहाँ की गंगा आरती, मंदिरों की घंटियाँ, घाटों की शांति और गलियों की चहल-पहल मिलकर ऐसा अनुभव प्रदान करती हैं, जो जीवन भर स्मरणीय रहता है। इस प्रकार वाराणसी पर्यटन, धर्म, संस्कृति और इतिहास का अद्वितीय संगम है—एक ऐसी नगरी जहाँ हर क्षण में आध्यात्मिकता का स्पर्श है और हर आगंतुक अपने भीतर एक नई चेतना लेकर लौटता है।

प्राचीनता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वाराणसी का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है—अर्थात वह भूमि जिसे स्वयं भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। मान्यता है कि इस नगरी की स्थापना स्वयं शिव ने की थी। यह नगर सदियों से ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहाँ अनेक आश्रम और गुरुकुल थे, जहाँ वेद, दर्शन और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल में भी यह शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रहा।

काशी विश्वनाथ मंदिर

वाराणसी का हृदय कहे जाने वाला यह मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को विश्वनाथ यानी संपूर्ण विश्व के नाथ के रूप में पूजा जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप भव्य है और इसका परिसर विस्तृत एवं सुव्यवस्थित है। सावन, महाशिवरात्रि और देव दीपावली के अवसर पर यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है।

मोक्ष की नगरी

हिंदू धर्म में वाराणसी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए देश-विदेश से अनेक श्रद्धालु जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ निवास करते हैं।

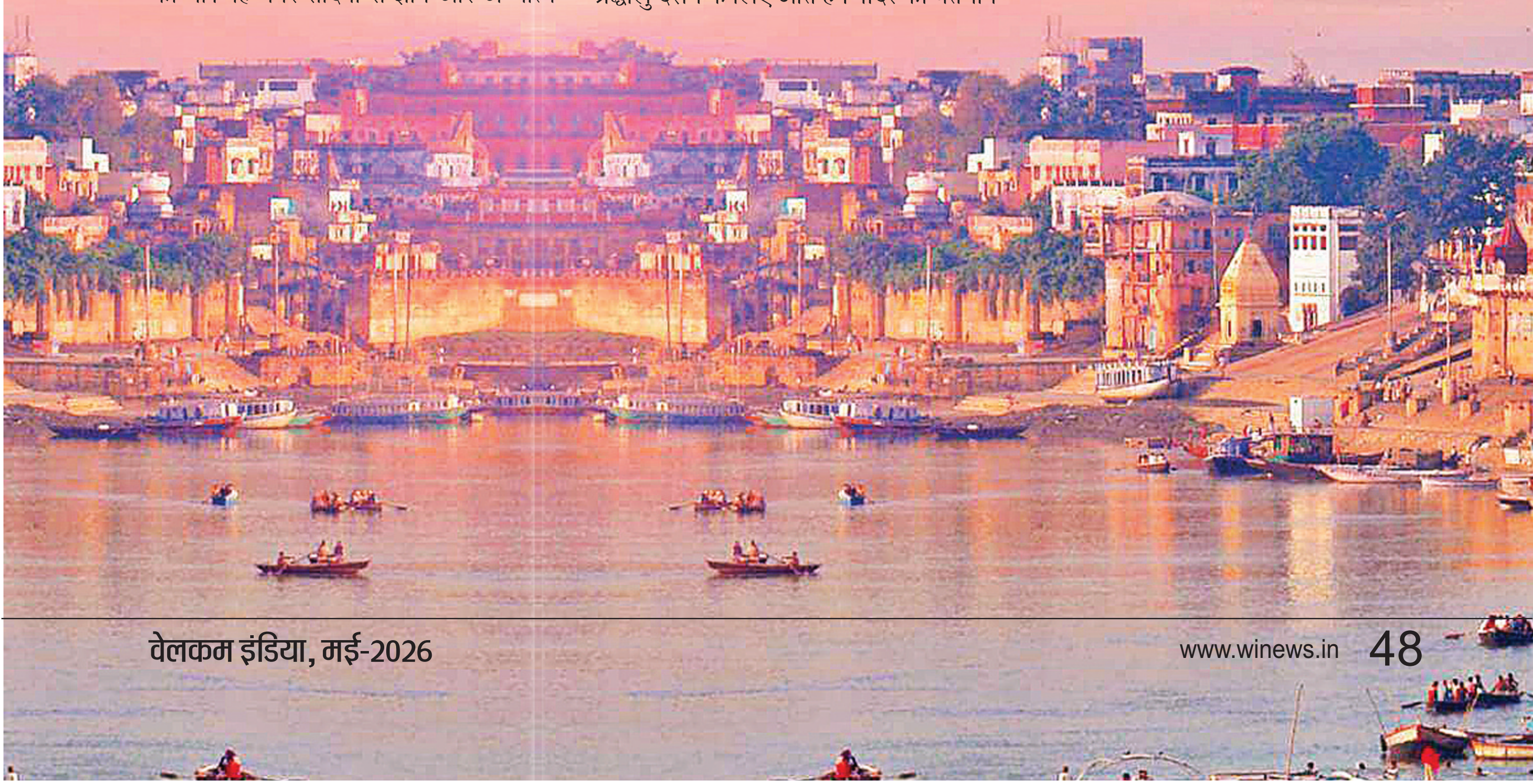

गंगा और घाटों का महत्व

वाराणसी की पहचान उसके घाटों से है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 84 घाट हैं। प्रत्येक घाट का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख घाट है, जहाँ प्रतिदिन भव्य गंगा आरती होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा ने यहाँ दस अश्वमेध यज्ञ किए थे। मणिकर्णिका घाट को श्मशान घाट है। यहाँ अंतिम संस्कार को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। अस्सी घाट युवाओं और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय, यहाँ प्रातःकालीन योग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गंगा स्नान, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्मकांड यहाँ पूरे वर्ष संपन्न होते रहते हैं।

शिक्षा का केंद्र

वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र

वाराणसी केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि संस्कृति और कला का भी केंद्र है। यह शहर शास्त्रीय संगीत की धरती है। महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से काशी की धुनों को विश्व तक पहुँचाया। बनारस घराना तबला, ध्रुपद और ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के त्योहारों और समारोहों में संगीत की विशेष भूमिका रहती है।

वाराणसी के पर्यटन स्थल

वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ प्रमुख पर्यटन स्थल है। वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ धमेख स्तूप, अशोक स्तंभ और बौद्ध मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह अत्यंत पवित्र स्थल है।

तुलसी मानस मंदिर

यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ अंकित हैं। संकटमोचन हनुमान मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ रहती है।

त्योहार और आयोजन

वाराणसी में वर्ष भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। देव दीपावली पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी घाट दीपों से जगमगा उठते हैं। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा होती है। नागनाथैया और रामलीला भी पारंपरिक आयोजनों में शामिल है।

रामनगर किला

गंगा के पूर्वी तट पर स्थित यह किला 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें प्राचीन वस्तुएँ, शस्त्र और राजसी पोशाकें संरक्षित हैं।

बनारसी जीवनशैली और खानपान

वाराणसी की पहचान उसकी गलियों और स्वादिष्ट व्यंजनों से भी है। यहाँ की प्रसिद्ध बनारसी पान, कचौड़ी-जलेबी, चाट और लस्सी पर्यटकों को विशेष आकर्षित करती है। बनारसी साड़ी अपनी बारीक कारीगरी और रेशमी बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियाँ संकरी होते हुए भी जीवंत हैं।

हर मोड़ पर मंदिर, दुकान या चाय की गुमटी मिल जाती है, जहाँ दर्शन और दर्शनशास्त्र दोनों पर चर्चा होती है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार के चलते सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यह शहर अच्छी तरह जुड़ा है। घाटों का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता अभियान और नई परियोजनाओं ने शहर को और आकर्षक बनाया है।

फैटी लीवर से कैसे बचें ?

जानिए 7 असरदार एक्सरसाइज और जरूरी टिप्स

डॉ. मुकुल शर्मा

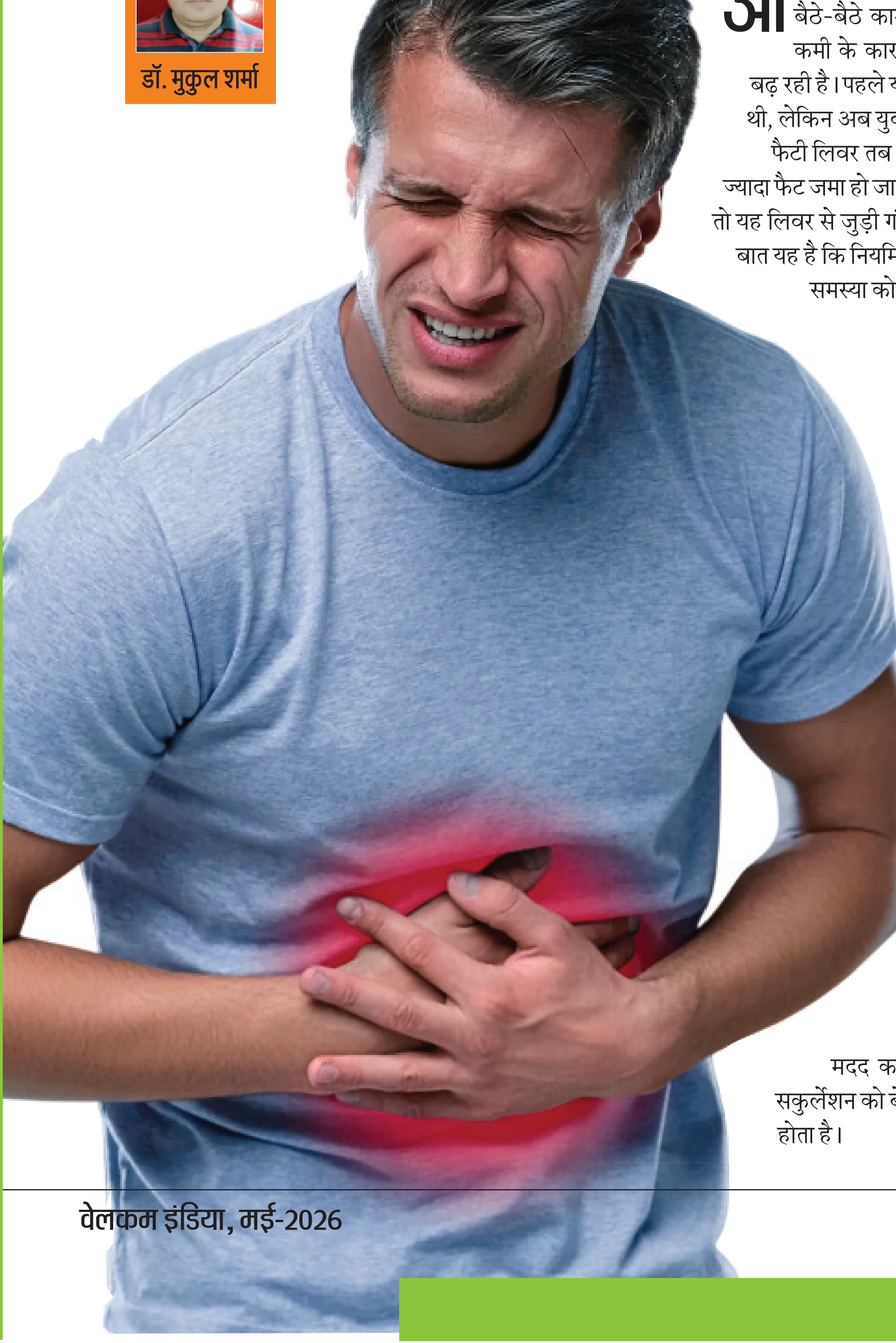

क्या है फैटी लिवर की समस्या

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गलत खानपान, लंबे समय तक बैठे-बैठे काम करने की आदत और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण Fatty Liver Disease की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले यह बीमारी ज्यादातर उम्रदराज लोगों में देखी जाती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं।

फैटी लिवर तब होता है जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। अगर समय रहते इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

फैटी लिवर में क्यों जरूरी है एक्सरसाइज

डॉक्टरों के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, वजन नियंत्रित रहता है और लिवर में जमा अतिरिक्त फैट कम करने में मदद मिलती है। सही एक्सरसाइज और संतुलित आहार से फैटी लिवर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

1. तेज चलना

तेज चलना सबसे आसान और प्रभावी एक्सरसाइज मानी जाती है। तेज गति से चलने से शरीर की कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और लिवर में जमा फैट कम होने में मदद मिलती है।

सलाह: रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलने की आदत डालें।

2. जॉगिंग

जॉगिंग शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करती है। यह वजन कम करने के साथ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे लिवर की सेहत में सुधार होता है।

3. साइक्लिंग

साइक्लिंग एक शानदार कार्डियो एक्सरसाइज है जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। इससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है, कैलोरी बर्न होती है और लिवर पर दबाव कम होता है।

4. स्क्वैट्स

स्क्वैट्स शरीर के बड़े मसल ग्रुप को सक्रिय करते हैं। इनके अभ्यास से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, फैट तेजी से बर्न होता है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है।

सलाह: रोज 3 सेट में 10-15 स्क्वैट्स करने की कोशिश करें।

5. प्लैंक

प्लैंक कोर मसल्स को मजबूत बनाने वाली बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके अभ्यास से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है और शरीर की स्थिरता बढ़ती है, जो फैट लॉस में सहायक है।

6. योग

योग शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करता है। रोजाना भुजंगासन, धनुरासन और कपालभाति जैसे योगासन करने से पाचन बेहतर होता है और लिवर की सेहत में सुधार हो सकता है।

7. स्विमिंग

स्विमिंग एक फुल-बॉडी वर्कआउट है जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद करता है। नियमित तैराकी से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है।

फैटी लिवर से बचने के लिए जरूरी टिप्स

फैटी लिवर की समस्या से बचने के लिए जीवनशैली में कुछ आसान बदलाव बेहद जरूरी हैं:

तला-भुना और ज्यादा मीठा खाने से बचें

- रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें
- वजन को नियंत्रित रखें
- शराब और जंक फूड से दूरी बनाएं
- दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
- स्वस्थ जीवनशैली ही सबसे बड़ा बचाव

फैटी लिवर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली। यदि समय रहते ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

'हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट' में शाहरुख खान की एंट्री, वैश्विक मंच पर बढ़ा किंग खान का कद

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने एक बार फिर प्रतिष्ठित Hurun Global Rich List में अपनी जगह बनाकर अपनी लोकप्रियता और आर्थिक ताकत का नया उदाहरण पेश किया है। इस सूची में शामिल होकर शाहरुख खान ने न केवल भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में अपनी पहचान और मजबूत की है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली कारोबारी हस्ती के रूप में भी अपना रुतबा बढ़ाया है।

दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह

'हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट' दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों की सूची मानी जाती है, जिसमें उद्योग, तकनीक, खेल और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल होती हैं। इस सूची में शाहरुख खान की मौजूदगी यह दर्शाती है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ बिजनेस जगत में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

फिल्मों के साथ बिजनेस में भी मजबूत पकड़

शाहरुख खान की कमाई का मुख्य स्रोत केवल फिल्में ही नहीं हैं, बल्कि कई सफल कारोबारी उपक्रम भी हैं। वे Red Chillies Entertainment के मालिक हैं, जो फिल्म निर्माण और वीएफएक्स के क्षेत्र में बड़ी पहचान रखती है। इसके अलावा वे Kolkata Knight Riders के सह-मालिक भी हैं, जो Indian Premier League की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है। इन व्यवसायों ने उनकी ब्रांड वैल्यू और आर्थिक ताकत को और मजबूत किया है।

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी होती है बड़ी कमाई

फिल्मों के अलावा शाहरुख खान कई बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। विज्ञापनों और एंडोर्समेंट के जरिए उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। लंबे समय से बॉलीवुड में सक्रिय रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

सिर्फ अभिनेता नहीं, सफल उद्यमी भी

विशेषज्ञों का मानना है कि शाहरुख खान की सफलता केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने मनोरंजन उद्योग को एक व्यवसायिक दृष्टि से भी आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि वे आज केवल एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में भी पहचाने जाते हैं।

भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की उपलब्धि

'हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट' में जगह बनाकर शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। उनकी यह उपलब्धि न केवल बॉलीवुड के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह भारतीय मनोरंजन उद्योग की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी दर्शाती है।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कब्जा!

छह देशों में बैन के बावजूद विदेशों में धुरंधर-2 ने उड़ाया गर्दा, कई देशों में बनी नंबर 1

प्रवीण सिंह कुशवाहा

रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar-2) को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 35 दिन पूरे हो चुके हैं। 19 मार्च को आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया है कि बाकी मेकर्स के मन में खौफ बैठ गया है और कोई भी इसके सामने अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। 'धुरंधर 2' जितनी स्पीड से भारत में दौड़ रही है, उससे कई गुना तेज रफ्तार से यह विदेशों में नोट छाप रही है। यह फिल्म किन 6 बड़े देशों में नंबर 1 बन चुकी है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ इसने 'बाहुबली 2' का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। द वायर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनाइटेड किंगडम (UK) में इस फिल्म ने हाल ही में शाहरुख खान (ShahRukh Khan) की 'पठान' को पटखनी देकर नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है।

55 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ यह मूवी वहां की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन चुकी है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस फिल्म ने 'पठान' और 'जवान' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और 77 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है। कनाडा की बात करें तो रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने अपनी ही फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां 68.50 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की है।

अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक बजा डंका

इन बड़े देशों के अलावा 'धुरंधर 2' न्यूजीलैंड में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। वहां इस मूवी ने अब तक कुल 7.1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं, जर्मनी में भी फिल्म का डंका बज रहा है और इसने 9 से 10 करोड़ रुपये के बीच का सॉलिड कलेक्शन किया है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो यहां 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले इस फिल्म ने वहां 'बाहुबली 2' का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और अब यह 233 करोड़ रुपये कमाकर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। यह फिल्म गल्फ कंट्रीज में बैन है।

'धुरंधर 2' की कुल ओवरसीज मार्केट में कमाई की बात की जाए, तो फिल्म ने अभी तक 471 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बिजनेस कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर किसी भारतीय फिल्म की यह सबसे तेज और सबसे ज्यादा कमाई है।

महमूद रजा
बिजनौर

एशियाई खेलों में पदक जीतना मेरा लक्ष्य: मीराबाई चानू

टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना इस साल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले एक दशक से अधिक समय से मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन का चेहरा रही हैं। उनके शानदार करियर में एशियाई खेलों का पदक ही एकमात्र ऐसी उपलब्धि है, जो अभी तक उनके खाते में नहीं जुड़ पाई है।

चानू के पास टोक्यो ओलंपिक का रजत, विश्व चैंपियनशिप के तीन पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में भी तीन पदक हैं। चानू ने यहां खेलो इंडिया जनजातीय खेलों (केआईटीजी) के उद्घाटन समारोह के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'एशियाई खेल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहां मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे यह और चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बन जाता है।' एशियाई खेलों में चानू का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2014 एशियाई खेलों में पदार्पण करते हुए नौवां स्थान हासिल किया था, जबकि पीठ की चोट के कारण उन्हें 2018 संस्करण से बाहर रहना पड़ा। वह 2022 एशियाई खेलों में पदक के सबसे करीब पहुंची थीं, लेकिन कूल्हे की चोट के कारण अहम समय पर उनका अभियान प्रभावित हुआ और वह पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। अब 31 वर्षीय चानू महाद्वीपीय प्रतियोगिता में संभवतः अपने अंतिम प्रयास की तैयारी कर रही हैं और उनका लक्ष्य अपने शानदार करियर में इस एकमात्र कमी को पूरा करना है। इस साल जुलाई-अगस्त में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों के बीच वजन संतुलन बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। वह राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किग्रा वर्ग में हिस्सा लेंगी, जबकि एशियाई खेलों के लिए फिर से 49 किग्रा वर्ग में वापसी करेंगी। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रमंडल खेलों तक अपना वजन 48 किग्रा के भीतर रखूंगी, लेकिन इसके दो महीने बाद ही एशियाई खेल हैं जो 49 किग्रा वर्ग में हैं, इसलिए मुझे फिर से बदलाव करना होगा।' चानू ने खेलो इंडिया

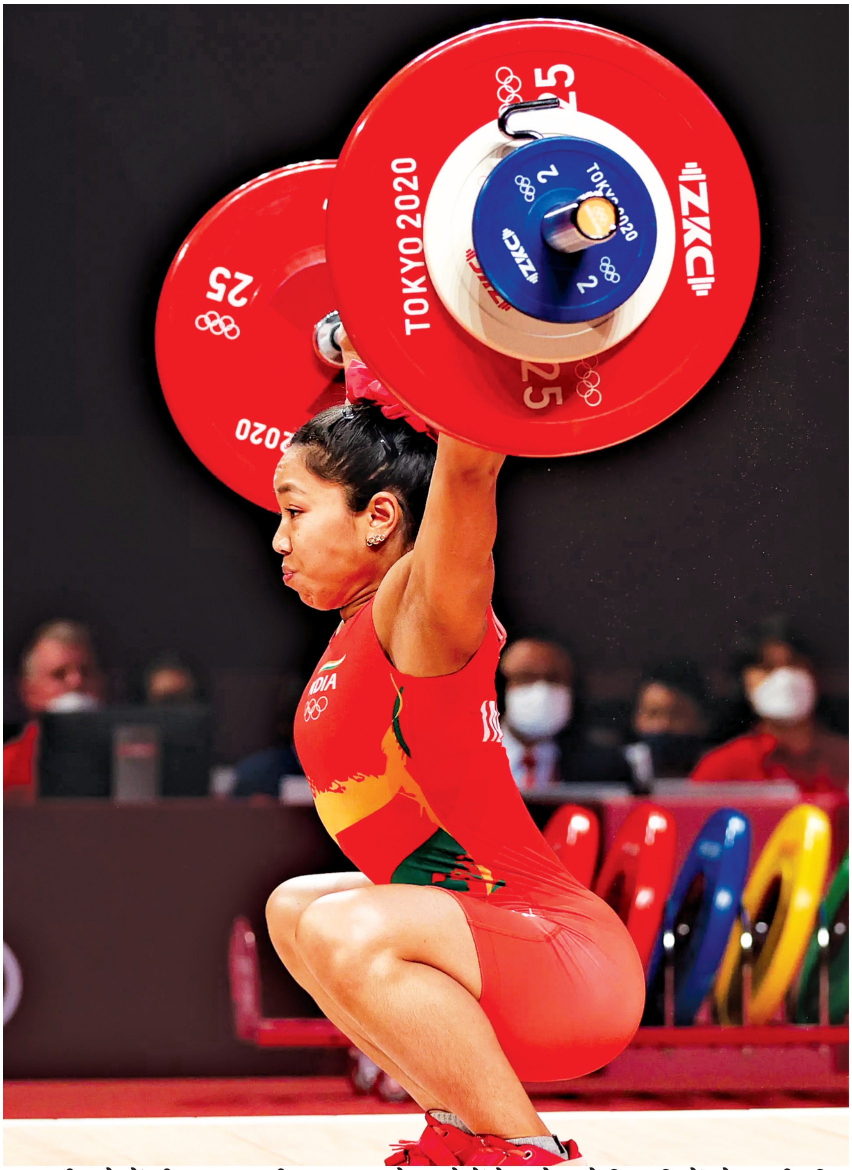

जनजातीय खेलों की शुरूआत की सराहना करते हुए इसे दूरदराज के इलाकों के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा, 'एक खिलाड़ी के तौर पर मेरे लिए यह गर्व का क्षण है कि सरकार केआईटीजी जैसी पहल को प्राथमिकता दे रही है। यह प्रतियोगिता दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देगी।' उन्होंने कहा, 'मैंने देशभर में, खासकर पूर्वोत्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जहां प्रतिभा तो है लेकिन ऐसे मंचों की कमी के कारण वह निखर नहीं पाती।

ऋषि सुनक भी हुए फैनः 11 साल की बोधाना ने रचा इतिहास

भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी Bodhana Sivanandan ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड की टॉप रैंक्ड महिला चेस प्लेयर बनकर सबको चौंका दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री Rishi Sunak ने भी खुलकर तारीफ की है।

ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोधाना के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनकी यह सफलता किसी सरप्राइज की तरह नहीं है। उन्होंने बताया कि वह पहले भी डाउनिंग स्ट्रीट गार्डन में बोधाना के साथ एक मुकाबला खेल चुके हैं, जिससे उन्हें उनकी प्रतिभा का अंदाजा पहले ही हो गया था। नॉर्थ लंदन में रहने वाली बोधाना ने 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूनामेंट्स में बेहतरीन खेल के दम पर उन्होंने कई बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। बोधाना के माता-पिता मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से हैं, जो 2007 में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। बेहद कम उम्र में ही बोधाना ने 2366 की प्रभावशाली रेटिंग हासिल कर ली है, जो उनके उज्ज्वल भविष्य का संकेत देती है।

उन्होंने चार बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन Lan Yao को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। यही नहीं, बोधाना अब विश्व की शीर्ष 100 महिला खिलाड़ियों में भी शामिल हो चुकी हैं और फिलहाल 72वें स्थान पर हैं। यह उपलब्धि न सिर्फ बोधाना के लिए, बल्कि पूरे

भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है। इतनी कम उम्र में उनका यह मुकाम आने वाले समय में उन्हें विश्व शतरंज के सबसे बड़े नामों में शामिल कर सकता है।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP,
TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER
(POSTPAID/PREPAID/
SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/
CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI
ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

TCL

Global TOP 1 Mini LED TV Brand
by the shipment market share of Mini LED TVs in 2024

SQD-Mini LED TV

X11L
The Pinnacle of Mini LED Tvs
239.5 cm (98) | 206 cm (85)

Up to 100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut | Super QLED | WHVA 2.0 Ultra Panel

Precise Dimming Series Up to 20,736 Zones | Up to HDR 10,000nits | Flat-thin Design

X11L RANGE STARTS FROM : ₹5,99,990-/-*

Discount applied as per T&C*

C7L SQD-Mini LED TV
Colors Pop Out
Audio by Bang & Olufsen
206 cm (85) | 185 cm (75)
160.8 cm (65) | 136 cm (55)

100% BT. 2020 All Scenes Wide Color Gamut | HVA 2.0 Pro Panel | Up to HDR 3000nits

288 VRR Game Accelerator | 2176 Precise Dimming Zones | Game Master

RANGE STARTS FROM : ₹89,990-/-*

Discount applied as per T&C*

P8L Premium QLED TV
Speed to Flow, Light to Glow
206 cm (85) | 185 cm (75)
160.8 cm (65) | 136 cm (55)

QD-Mini LED Dimming | 144Hz Native Refresh Rate

ONKYO 2.1 Hi-Fi System* | HVA Panel | TCL Ai

RANGE STARTS FROM : ₹52,990-/-*

Discount applied as per T&C*

P7L Premium QLED TV
Vivid and Vibrant
206 cm (85) | 185 cm (75) | 160.8 cm (65)
136 cm (55) | 126.5 cm (50) | 107.5 cm (43)

QLED | ONKYO 2.1 Hi-Fi System* | Slim & Uni-body

HVA Panel | TCL Ai | Google TV

RANGE STARTS FROM ₹ 34,990-/-*

Discount applied as per T&C*

P6L 4K SMART TV
Crystal Clear, Brilliantly Smart
185 cm (75) | 160.8 cm (65) | 136 cm (55)
126.5 cm (50) | 107.5 cm (43)

HDR 10 | Metallic Bezel-less | TCL Ai

HVA Panel | Dolby Audio | Google TV

RANGE STARTS FROM : ₹31,990-/-*

Discount applied as per T&C*

BAJAJ FINSERV | IDFC FIRST Bank | HDB FINANCIAL SERVICES | HDFC BANK | TVS CREDIT | Chola Enter a better life | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | ICICI Bank | kotak Kotak Mahindra Bank | YES BANK

*T&C Discount and cashback applies depend on product and models as per company T&C

Haryana : Suresh Chandra-7011099802
Punjab : Sanjay Khurana-9780041403
UP-Lucknow : Juned Ahmad Khan-7897554445

UP-Varanasi : Ram Kumar Mishra-9838109000
UP-Meerut : Sunil Sharma-9910349974
Uttrakhand : Sourav Upadhyay-7895700555